राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 234 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार ,17 फरवरी 2021 , मूल्य रु. 1.50

कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश, कुछ लोग नहीं चाहते किसानों की आमदनी बढ़े

लखनऊ । देश की आजादी में बड़ी भूमिका अदा करने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सम्मान दिया। बहराइच में मंगलवार को महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल की आधारशिला रखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौरा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री को राजा सुहेलदेव की अश्वारोही प्रतिमा पयागपुर रियासत के यशवेंद्र प्रताप सिंह ने भेंट की। मुख्यमंत्री के दीप पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से व उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले, राष्ट्रनायक महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, उस पावन धरती बहराइच को नमन करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वसंत पंचमी की सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज को एक नया भवन भी मिला है। यह बहराइच के जीवन के लोगों को आसान बनाएगा। इसका लाभ आसपास के श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर के साथ ही नेपाल से आने वाले मरीजों को भी मिलेगा।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ वह नहीं है, जो देश को गुलाम बनाने वालों या गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा है। भारत का इतिहास वो भी है, जो भारत के सामान्य जनने, लोकगाथाओं में रचा-बसा है। जिसे पीढ़ियों ने आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहते हैं।

महापुरुषों का त्याग, उसकी तपस्या, उनका संगम, उनकी वीरता, शहादत का स्मरण करना व उनसे प्रेरणा प्राप्त करना, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होगा। यह दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन से मर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक-नायिका को वह स्थान नहीं दिया था, जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने वालों के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे आज का भारत सुधार रहा है।

पीएम ने कहा कि नेता जी सुभाष चंद्र बोस, जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, वे या उनकी इस पहचान व योगदान को महत्व दिया गया। जो उनको मिलना चाहिए। आज हमने उनकी इस पहचान को अंडमान और निकोबार तक देश-दुनिया के सामने सशक्त किया है। हमने नेता जी सुभाष चंद्र बोस की पहचान को देश-दुनिया के सामने सशक्त किया।

देश की 500 से भी अधिक रियासतों को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या किया गया, यह बात देश का बच्चा-बच्चा जानता है।

आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की है, जो हमें प्रेरणा देती है। देश के संविधान देने वालों में अहम भूमिका देने वाले वंचित, पीड़ित, शोषित के आवास डा. बाबा साहब अंबेडकर को भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा है। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डा. बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है।

चौरी-चौरा के वीरों की तरह महाराजा सुहेलदेव के साथ व्यवहार हुआ- चौरी-चौरा के वीरों के साथ जो हुआ भूलने योग्य नहीं। महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। इतिहास की किताबों में भले ही उनके शौर्य पराक्रम व उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं व हृदय में वो हमेशा बने रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर एक बार फिर किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों ने किसानों की जमीन छीन ली, वो नहीं चाहते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़े। हमारी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है।

पीएम मोदी ने रामचरित मानस की एक चौपाई सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। हृदयं राखि कोसलपुर राजा। मंत्र का अर्थ- अयोध्यापुरी के राजा राम को हृदय में रखकर जो कुछ काम करेंगे उसमें अवश्य सफलता मिलेगी।

वहीं, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम का सबसे पहले स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच के लिए आज अहम दिन है। आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिएअपने शौर्य पराक्रम का प्रर्दशन इस धरती पर करने वाले धर्मरक्षक, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव की जंयती का कार्यक्रम भी है।

उन्होंने बताया कि आज से करीब 4 वर्ष पहले बहराइच में इस क्षेत्र की आरोग्यता के लिए पीएम मोदी द्वारा एक मेडिकल कॉलेज दिया गया था। अब वह बनकर तैयार हो गया है। जिसका नाम महाराज सुहेल देव के नाम पर ही रखा है। आज इस मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। वहीं, कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों से गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दलित, शोषित, वंचित गांव, गरीब किसान, जो कि किसान का हक मार रहा था, उनको लूटा जा रहा था, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचने नहीं दे रहा था।

तब इस राज्य के अंदर एक ईमानदार, कर्मठ, दलितों से प्रेम करने वाला, महिलाओं के सम्मान के लिए, इस राज्य के खुशहाली के लिए योगी आदित्यनाथ के रूप में राज्य को मुख्यमंत्री मिला। सप्ताह के सात दिन व दिन के 24 घंटे अथक परिश्रम व परिश्रम की पराकाष्ठा गरीबों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाया।

मध्यप्रदेश : नहर में गिरी बस, 45 की मौत

भोपाल, (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के सीधी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 54 यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। अब तक 45 शव मिल चुके हैं। 7 लोग बचा लिए गए। ड्राइवर खुद तैरकर बाहर आ गया। उसे हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। कुछ शवों के बह जाने की बात भी सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है।

बस सीधी से सतना जा रही थी। हादसा रामपुर के नैकिन इलाके में सुबह करीब 7.30 बजे हुआ। हादसे के चार घंटे बाद 11.45 बजे क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। नहर की गहराई 20 से 22 फीट बताई जा रही है। जिस वक्त हादसा हुआ, तब बहाव तेज था, लिहाजा यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। मृतकों में 12 छात्र भी थे।

पुलिस के मुताबिक, बस में 32 लोग बैठाए जा सकते थे, लेकिन इसमें 54 यात्री भर लिए गए। बस का मालिक कमलेश्वर सिंह है जो हादसे के बाद से फरार है। बस सीधी से सतना आ रही थी। 80 किमी का सफर तय करने के बाद ये बाणसागर नहर में जा गिरी। बस की फिटनेस 2-5-21 तक है और बस का परमिट 12-5-25 तक का था। सरकार जब किसी बस को परमिट देती है, उसी समय उसका रूट भी तय कर दिया जाता है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक तय रूट से अलग रास्ते पर बस संचालन अपराध माना जाता है। सीधी बस दुर्घटना की एक वजह यह भी है कि हादसे का शिकार होने वाली बस के ड्राइवर ने अचानक ही इसका रूट बदल दिया था। ट्रैफिक जाम के कारण ड्राइवर ने रास्ता बदला और 7 किलोमीटर तक नए रूट से बस को ले गया।

बस को सीधी मार्ग पर छुहिया घाटी से होकर सतना जाना था, लेकिन यहां जाम की वजह से ड्राइवर ने रूट बदल दिया। वह नहर के किनारे से बस ले जा रहा था। यह रास्ता काफी संकरा है। इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया।

हादसे में बचे यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर काफी स्पीड में बस चला रहा था। लोगों ने उससे कई बार रफ्तार कम करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। इसी दौरान उसने कंट्रोल खोद दिया और बस नहर में गिर गई। जितने भी लोग बस से बाहर आ पाए वे सभी पीछे की सीटों पर बैठे थे। बस के नहर में डूबने के दौरान उन्हें थोड़ा सा वक्त मिला जिससे वे बाहर आ गए और तैरकर किनारे पहुंचे।

सीधी में बस हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक को स्थगित कर दिया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल भोपाल से हेलीकाप्टर से रीवा पहुंचे और यहां से घटनास्थल पहुंचकर लोगों को सांत्वना दी। मंत्रियों ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। उधर, हादसे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के साथ बैठक की है। बैठक में बताया गया कि सीधी से सतना के बीच चलने वाली बसें सुबह के समय खाली ही जाती हैं लेकिन मंगलवार को एनटीपीसी का एग्जाम था। रीवा और सतना में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 32 सीटर बस में ज्यादा युवा ही थे, वह परीक्षा देने रीवा और सतना आ रहे थे।

जेपी नड्डा ने बुलाई यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भाजपा नेताओं की बैठक

नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बैठक में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह बैठक नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन से निपटने के लिए आगे की रणनीति बनाने को लेकर हो रही है। किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 83वें दिन भी जारी है। इस बीच किसानों को मनाने के लिए अब तक केंद्र सरकार की ओर से की गई सभी कोशिशें बेनतीजा रही हैं।

बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों - द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं। केन्द्र सरकार इन कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे।

हम सबने मिलकर पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया : केजरीवाल

नई दिल्ली, (संवाददाता)। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपने एक साल पहले अपने बेटे को एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया और हम सबने मिलकर पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रौशन किया। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक और ऑक्सीमीटर जैसे कामों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लाखों दिल्लीवासियों को खाना खिलाया, फ्री राशन बांटा और रास्ते में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने तमाम चुनौतियों के बीच फ्री बिजली व पानी योजना को जारी रखा और सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 98 प्रतिशत रिजल्ट लाकर दिल्ली वालों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। यह दो करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है, जो 24 घंटे दिल्ली वासियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है और करती रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने

कार्यकाल के एक साल पूरे होने वीडियो संदेश जारी किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक साल पहले आप सबने एक बार फिर अपने बेटे को आप की सेवा करने का एक और मौका दिया। यह बहुत कठिन साल था, लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलकर एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रौशन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलकर शानदार काम करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक और ऑक्सीमीटर, इन जैसे कामों की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लाखों दिल्लीवासियों को खाना खिलाया। लोगों को फ्री राशन बांटा और रास्ते में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाया।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन तमाम चुनौतियों के बीच आप की सरकार ने फ्री बिजली और पानी की योजना को जारी रखा। इन सब के बीच हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में 98 प्रतिशत रिजल्ट लाकर दिल्ली के दो करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आपकी सरकार ने इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए किसानों को पराली का समाधान भी दे दिया है। अब दिल्ली के किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ती है। दिल्ली की तरक्की के इन 6 सालों में गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलने लगा है और 24 घंटे बिजली आने लगी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह दो करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है, जो 24 घंटे और सातों दिन दिल्ली वासियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है और यूं ही करती रहेगी। बस, आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी तरह से आपकी सेवा में लगा रहूंगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया ई-छावनी पोर्टल लोगों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, (संवाददाता)। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत पूरी दुनिया के लिए संभावनाओं का देश बन गया है। चाहे रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, कृषि हो, व्यापार हो या फिर आईटी क्षेत्र, विश्व भारत की एक नई छवि देख रहा है। भारत को लेकर पहले जो धारणा थी, वो बीते कुछ वर्षों में अब बदल चुकी है। ये बात रक्षा संपदा भवन में आयोजित ई-छावनी पोर्टल के लोकार्पण समारोह के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक आर्थिक विकास की भरपूर कोशिश कर रही है। साथ ही शासन प्रणाली व प्रक्रिया में बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार प्रयासरत है। ताकि इज आफ लिविंग और इज आफ डूइंग के माध्यम से सरकार जनता को सुविधा दे सकें। रहने की सुविधा, कुछ करने की सुविधा लोगों को प्राप्त हो। उन्होंने ई-छावनी पोर्टल के लोकार्पण की सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई दी। मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिम गवर्नेंस माडल का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ई-छावनी पोर्टल अच्छे शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इससे छावनी के निवासियों की काफी समस्याओं का समाधान होगा।

पैंगोंग लेक से पीछे हटने लगी चीनी सेना, टैंट उखाड़े जा रहे, टैंक भी जा रहे पीछे

नई दिल्ली, एजेंसियां। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारे से चीन और भारत की सेनाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पीछे हट रही हैं। इस प्रक्रिया के पूरे होने में छह-सात दिन और लगेंगे। यह जानकारी रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने बताया कि पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे से चीन की सेना बंकर, अस्थायी चौकियां और अन्य निर्माण ध्वस्त करते हुए पीछे हट रही है। चीनी जवानों की तादाद भी लगातार कम हो रही है। समाचार एजेंसी एएनआइ ने भारतीय सेना की उत्तरी कमान के हवाले से इसका फोटो और वीडियो शेयर किया है।

सूत्रों ने बताया कि दोनों तरफ के कमांडर हर दिन मुलाकात कर सेना हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। दोनों देशों के बीच सेना हटाने पर नौ दौर की उच्चस्तरीय वार्ताओं के बाद पिछले हफ्ते ही सहमति बनी थी। बता दें कि दोनों देशों के बीच बनी सहमति के अनुसार चीन को फिंगर ऐट के आगे सिरीजाप चौकी पर अपनी फौज को ले जाना है। वहीं भारतीय सेना को फिंगर टू-थ्री के बीच स्थित चौकी धन सिंह थापा पर लौटना है। कई साल से यही भारत की स्थायी चौकी है। दोनों देशों की सेनाओं की गश्त और अन्य गतिविधियां अस्थायी तौर पर बंद रहेंगी।

पैंगोंग झील के किनारे पहाड़ की आकृति अंगुलियों की तरह दिखती है। यही वजह है कि इन्हें फिंगर कहा जाता है। इनकी संख्या आठ है। भारत का दावा फिंगर ऐट तक है। चीन के फिंगर फोर तक दावे से विवाद पैदा हो गया। पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर फोर और फिंगर ऐट के बीच आठ किलोमीटर का फासला है। यहां दोनों सेनाओं के बीच कई बाब भिड़ंत हो चुकी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार फिंगर फोर से चीनी सैनिकों की तादाद में काफी कमी आई है। एलएसी पर यथास्थिति बदलने के लिए चीन ने फिंगर फोर और पैंगोंग झील के दक्षिण में भारी संख्या में जवान और अन्य साजोसामान तैनात कर दिया था। झील से चीन की सेना अपनी नांव भी हटा रही है। पिछले साल तनाव बढ़ने के बाद उसने फिंगर ऐट से आगे इन्हें तैनात किया था।

गश्त फिर से शुरू होगी

जानकारी के अनुसार एक बार सेनाओं के पीछे चले जाने के बाद राजनयिक और सैन्य बातचीत होंगी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद ही गश्त फिर से शुरू होगी।

बता दें कि पैंगोंग झील के दक्षिण में जहां दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने-सामने थीं, वहां से भी सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। यहां कुछ स्थानों पर दोनों देशों के टैंक मात्र 100 मीटर के फासले पर तैनात थे। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण पर करीब दस महीने तक सैन्य गतिरोध रहा।

सड़क परिवहन मंत्रालय वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में कर रहा काम- नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को यहां कहा कि ईंधन के बढ़ते दाम को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिथियम ऑयन और हाइड्रोजन सेल जैसे वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में संभावना टटोलने के लिये कदम उठाया है।

केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में चमड़ा संकुल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एल्युमीनियम ऑयन और स्टील ऑयन बैटरी पर भी चर्चा की जा रही है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री गडकरी ने कहा, मेरा सुझाव यह है कि देश में वैकल्पिक ईंधन अपनाने का समय है। मैं भारत में अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के साथ ईंधन के रूप में इसके उपयोग पर जोर देता रहा हूं और अब 81 प्रतिशत लिथियम ऑयन बैटरी भारत में बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय हाइड्रोजन ईंधन सेल विकिसत करने के कार्य में भी लगा है। गडकरी ने कहा, हम जीवाश्म ईंधन के विकल्प पर काम कर रहे हैं। क्योंकि यह देश के लिये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल देश 8 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन का आयात करता है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि वैश्विक बाजार में जीवाश्म ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं और भारत में 70 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन का आयात होता है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में जैव-सीएनजी संचालित ट्रैक्टर को पेश किया। इसमें ईंधन के रूप में पराली, गन्ने की खोई, कपास फसल के अवशेष का उपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमें वैकल्पिक ईंधन उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है और तमिलनाडु कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य है। मंत्री ने कहा कि मैं राज्य सरकार से कृषि अवशेषों से ईंधन बनाने और किसानों को उससे अधिक आय प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं। फास्टैग अनिवार्य किये जाने की समयसीमा आगे बढ़ाये जाने के बारे में पूछे जाने उन्होंने कहा, इसमें कोई विस्तार नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस ने मनाया स्थापना दिवस

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। दिल्ली पुलिस के न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सलामी ली। इस मौके पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्वत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सराहनीय तरीके से उडश्क्क़19 लॉकडाउन से निपटा। 'दिल की पुलिस' का खिताब अर्जित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलिस बल के प्रयासों की सराहना की है। हमने इस दौरान 34 पुलिस कर्मियों को खो दिया, जो बेहद दुखद रहा।

दरअसल, दिल्ली पुलिस के पहले प्रमुख डीडब्ल्यू मेहरा को 16 फरवरी को नियुक्त किया गया था। इसलिए यह दिन दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 1978 में दिल्ली पुलिस एक्ट पारित होने पर जे.एन. चतुर्वेदी दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त नियुक्त किए गए थे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस को 74वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया है-' @ऊ/ढङ्ग्री के 74वें स्थापना दिवस पर सभी कर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। विपरीत परिस्थितियों में भी देश की राजधानी की सुरक्षा व शांति-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः समर्पित दिल्ली पुलिस के बहादुर जवानों के साहस, संयम व संकल्प को सलाम करता हूं।'

गौरतलब है कि वर्ष 1966 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस की समस्याओं को सुलझाने के लिए जस्टिस डीसी खोसला की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस आयोग का गठन किया गया और इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को पुनर्गठित किया गया और इसे चार जिलो में बांट दिया गया था। दिल्ली पुलिस की ताकत वर्तमान में 80,000 से भी ज्यादा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस में 3 रेंज, 11 जिले और 180 पुलिस स्टेशन हैं।

फर्जी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर चीन में हो रही है कार्रवाई, दर्जनों की हुई गिरफ्तारी

शंघाई। चीन में कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी धांधलियों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। इस क्रम में फर्जी कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रोडक्शन और इसके वितरण को लेकर दर्जनों लोगों

को गिरफ्तार किया गया है। 21 वैक्सीन संबंधित मामलों में बुधवार तक चीन में 70 संदिग्धों को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से अधिकतर मामलों की शुरुआत वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही हो गई थी। शिन्हुआ न्यूज के अनुसार, फर्जी वैक्सीन के 58 हजार खुराक में सलाइन सॉल्यूशन या मिनरल वॉटर भरकर ग्रुप ने 18 मिलियन युआन यानि 2.8 मिलियन डॉलर तक की कमाई की।

भारत के एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए क्यों

इस्लामाबाद। एक भारतीय एयर एम्बुलेंस को इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन(इमरजेंसी) लैंडिंग करनी पड़ी। एक भारतीय एयर एम्बुलेंस ने रविवार को इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के लिए आपातकालीन लैंडिंग की। पाकिस्तान के दुनिया न्यूज के अनुसार, एक भारतीय एयर एंबुलेंस ने पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) से संपर्क किया और इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने की अनुमति का अनुरोध किया, क्योंकि उसके विमान में ईंधन कम था। एक ब्रिटिश मरीज, एक डॉक्टर और दो नर्सों के साथ भारत का ये एयर एम्बुलेंस भारत के कोलकाता से तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे जा रहा था। दुनिया न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) से अनुमति मिलने के बाद भारतीय एयर एम्बुलेंस इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। हालांकि, यह दो घंटे में ईंधन भरने के बाद यहां से दोबारा रवाना हो गया।

किसी घटनास्थल से या किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, जहां मरीज की जान बचाने के लिए अति-आवश्यक इलाज के लिए कम समय में ले जाना के लिए बुनियादी चिकित्सीय सुविधाओं से परिपूर्ण हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर को एयर एंबुलेंस कहा जाता है। इसको आसान भाषा में समझें तो एयर एंबुलेंस वो हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर होता है, जिसमें वो सभी सामान और सुविधाएं होती हैं, जो कि किसी आपात स्थिति में समय रहते किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसे एक स्थान या अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए जरूरी होता है। इसका उपयोग खासतौर पर, मरीज की गंभीर स्थिति में कम समय में ज्यादा लंबी दूरी तय करने और सड़क मार्ग पर होने वाली भीड़भाड़ से बचने के लिए एयर एंबुलेंस का उपयोग किया जाता है। एयर एंबुलेंस को विभिन्न इमरजेंसी स्थितियों में कई फायदे प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए, एयर एंबुलेंस के फायदे जानते हैं।

एयर एंबुलेंस के अंदर क्या-क्या होता है ?

एयर एंबुलेंस के अंदर किसी भी इमरजेंसी स्थिति में इस्तेमाल किए जाने वाले जरूरी उपकरण होते हैं। इन उपकरणों में ब्रीदिंग एप्रेटस, मॉनिटरिंग सिस्टम, पेसमेकर आदि होते हैं। इसमें एड्रेनलीन, प्रोपोफोल, बीटा ब्लॉकर्स, खून पतला करने वाली मेडिसिन भी रखी होती हैं।

म्यांमार की सड़कों पर बख्तरबंद वाहन तैनात, सेना ने पूरी तरह से बंद किया इंटरनेट

नेपीता। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट में खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। नागरिक शासन बहाल करने की मांग को लकेर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर जुट रहे हैं। लोगों के विरध प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना से सोमवार को प्रमुख शहरों में बख्तरबंद वाहनों को तैनाती की है। इसके साथ ही देर रात 1 बजे से इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

अल जज़ीरा ने बताया कि लगातार नौ दिन से लगातार हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रमुख खहरों में सैन्य वाहन गस्त लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, रविवार शाम को बख्तरबंद वाहनों को यांगून, मायित्किना और सिटवे में देखा गया। इससे पहले, सैनिकों को उत्तरी राज्य काचिन में बिजली संयंत्रों में तैनात किया गया था, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी झड़प भी हुई। लोगों का मानना ??है कि सेना बिजली काटने के इरादे से वहां गई है। सैन्य शासन के बावजूद म्यांमार में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें यांगून और अन्य प्रमुख शहर भी शामिल हैं। इस बीच म्यांमार में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से सुरक्षित स्थनों पर रहने की अपील की है, क्योंकि 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार शहरों में बख्तरबंद वाहनों को घुमाया जा रहा है। दूतावास ने यह भी कहा कि रात 1 से 9 बजे के बीच दूरसंचार सेवाएं बंद रह सकती हैं।

इमरान की फजीहत: पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शोएब बोले-

हमारा प्रधानमंत्री नाकारा और नालायक, मोदी से उनकी तुलना नहीं हो सकती

इस्लामाबाद। किसी वक्त प्रधानमंत्री इमरान खान के पक्ष में नजर आने वाले पूर्व फौजी अफसर भी अब उनका सख्त विरोध करने लगे हैं। इमरान की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) अमजद शोएब ने इमरान का नाकारा और नालायक तक कह दिया। हालांकि, इस पूर्व फौजी अफसर ने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद का बचाव किया।

अमजद शोएब पाकिस्तान के लिए जाना-पहचाना नाम है। वे मुल्क के लगभग हर न्यूज चैनल पर आर्मी और फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट के तौर पर नजर आते हैं। शोएब अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इसके पहले तक वे खुले तौर पर इमरान और फौज का बचाव

करते आए हैं।

हाफिज सईद का मामला भारत की देन: एक सवाल के जवाब में शोएब ने कहा- अमेरिका ने हाफिज सईद के सिर पर ईनाम घोषित किया। यहां अपना एजेंट रेमंड डेविस भेजा। उसके जरिए वो मुंबई हमले में हाफिज सईद की भूमिका के सबूत हासिल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दरअसल, हाफिज सईद का मामला भारत के दबाव में जिंदा रखा जाता है।

सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए इस पूर्व फौजी अफसर ने कहा- पिछले साल अमेरिका ने शक के आधार पर हमारी हबीब बैंक के तमाम ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी। दिक्कत देश के अंदर है। हबीब बैंक और दूसरे संगठनों पर अमेरिका में कार्रवाई होती है, हमारे देश में क्यों नहीं। हमने किसी को सजा क्यों नहीं दी। हमने इतनी कोताहियां कीं, इसका कोई हिसाब भी नहीं दे सकता।

हुकूमत एक व्यक्ति की गुलाम

शोएब ने इमरान का नाम लिए बिना खूब खरी-खोटी सुनाई। एक सवाल के जवाब में कहा- सच्चाई ये है कि हुकूमत एक नाकारा और नालायक आदमी के हाथ में दे दी गई है। या ये कहें कि हुकूमत उसकी गुलाम बना दी गई है। पूरी दुनिया अपने मुल्क के लिए काम कर रही है, और ये हुकूमत इस नालायक आदमी के लिए काम कर रही है। लोगों को यह यकीन दिलाने में लगा दिया गया है कि हमारा तो यही प्रधानमंत्री है। जो लीडर्स अपने मुल्क के लिए काम करते हैं उनका पर्सनल एजेंडा या जाति नहीं होती। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमैसी फ्लॉप है, क्योंकि हमारे वजीर-ए-आजम को कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसे आदमी की तुलना आप नरेंद्र मोदी से कैसे कर सकते हैं?

इमरान के मंत्री का बेतुका बयान: शेख राशिद ने कहा-

प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस इसलिए छोड़ी, क्योंकि इनका टेस्ट करना जरूरी था

इस्लामाबाद। इमरान सरकार का विरोध कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख राशिद अहमद ने बेतुका बयान दिया है। रावलपिंडी के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर आंसू गैस के गोले इसलिए छोड़े गए, क्योंकि काफी वक्त से इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसलिए इनका टेस्ट जरूरी था।

दरअसल, इमरान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैलियां निकाली गईं और अब सरकारी कर्मचारी भी सड़कों पर उतर आए हैं। 10 फरवरी को हुई एक रैली के दौरान कर्मचारियों पर टियर गैस छोड़ी गई थी।

सैलरी बढ़ाई तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा- शेख राशिद

शेख राशिद ने सफाई भी दी कि आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल काफी काम संख्या में किया गया था ताकि भीड़ को तितर-बितर किया जा सके। दरअसल, दिक्कत प्रदर्शन या टियर गैस के गोले छोड़े जाने की नहीं थी, बल्कि सैलरी में इजाफे की थी। ऐसे समय जब देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं और महंगाई दर काफी बढ़ती जा रही है, तो सैलरी बढ़ाने से सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा। कर्मचारी इमरान सरकार से महंगाई को

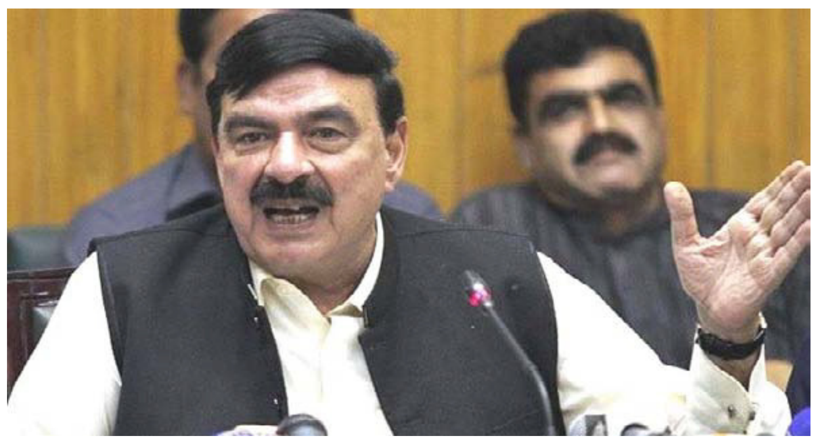

देखते हुए सैलरी और पेंशन में इजाफा करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वे तब तक सचिवालय के बाहर बैठे रहेंगे, जब तक सरकार इस पर सही फैसला नहीं ले लेती है।

किसी और देश का मंत्री ऐसा बोलता तो कुर्सी चली जाती- विपक्ष

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जादारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने प्रदर्शन का समर्थन किया था। मरियम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित करना बंद करना चाहिए। वहीं, मरियम की ही पार्टी के मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अगर किसी और देश में किसी मंत्री ने इस तरह का बयान दिया होता, तो उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया जाता और उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ती।

कोरोना दुनिया में: ब्रिटेन में 1.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन; इजराइल में रोज 2000 विदेशी यात्रियों के आने की मंजूरी

लंदन। ब्रिटेन में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि कहा कि यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। वैज्ञानिकों, फैक्ट्री वर्कर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, NHS स्टाफ, वॉलंटियर्स और जिन्होंने इस आश्चर्यजनक उपलब्धि को संभव बनाया, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया।

यके में 8 दिसंबर को शुरू हुआ था वैक्सीनेशन

ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत 8 दिसंबर को हुई थी। 90 साल की बुजुर्ग मारग्रेट कीनन पहली ब्रिटिश नागरिक थीं, जिन्हें फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। यहां फिलहाल फाइजर-बायोटेक और एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना महामारी के बीच इजराइल में सरकार ने कुछ रियायत देना शुरू किया गया है। यहां अब रोजाना 2000 विदेशी एयर पैसेंजर्स को आने की मंजूरी दे दी गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री को यहां आने वाले पैसेंजर्स को होटल में क्वारैंटाइन करने की जिम्मेदारी

टॉप-10 देश, जहां अब तक सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए

देशसं	क्रमित	मौतें	ठीक हुए
अमेरिका	28,261,470	497,174	18,224,288
भारत	10,916,172	155,764	10,619,083
ब्राजील	9,834,513	239,294	8,745,424
रूस	4,071,883	80,126	3,593,101
च	4,038,078	117,166	2,160,515
फ्रांस	3,465,163	81,814	238,753
स्पेन	3,056,035	64,747	ह्व/
इटली	2,721,879	93,577	2,225,519
तुर्की	2,586,183	27,471	2,475,329
जर्मनी	2,341,701	65,566	2,119,100

सौंपी गई है। यहां कोरोना पर कंट्रोल के लिए 25 जनवरी से एयर ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण का नया वैरिएंट जल्द ही दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। इस वैरिएंट से उबरने में दुनिया को कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा संक्रामक ब्रिटेन के केंट क्षेत्र में फैले कोरोना वैरिएंट को बताया जा रहा है। जेनेटिक सर्विलांस प्रोग्राम के प्रमुख शेरोन ने वायरस के म्यूटेशन पर चिंता जताते हुए कहा कि इस नए स्ट्रेन के कारण ब्रिटेन में फिर से लॉकडाउन लगने की आशंका है। यह वैरिएंट 50 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। जानकारों का दावा है कि यह पहले वाले वैरिएंट से 70त्न ज्यादा तेजी से फैलता है और करीब 30त्न ज्यादा घातक हो सकता है। दुनिया में अभी कोरोना के 10.9 करोड़ केस आ चुके हैं। इनमें से 8.14 करोड़ मरीज ठीक हो चुके हैं। 24.11 लाख लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में रविवार को कुल 64,297 नए मरीज मिले और 1,111 लोगों की मौत हो गई। यहां अब तक 2.82 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1.82 करोड़ लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4.97 संक्रमितों ने जान गंवाई है।

वुहान से ही फैला कोरोना: रिपोर्ट में दावा- डब्ल्यूएस को वुहान से ही वायरस फैलने के संकेत मिले; जल्द ही प्रारंभिक रिपोर्ट पेश होगी

वाशिंगटन। कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने चीन गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम के हाथ अहम सबूत लगे हैं। टीम को इस बात के भी संकेत मिले हैं कि दिसंबर 2019 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस वुहान से ही फैला। एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया। इसके मुताबिक, टीम ने उन हजारों लोगों के ब्लड सैंपल तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है, जिनकी चीन ने अब तक जांच नहीं करने दी है।

डब्ल्यूएचओ की टीम के प्रमुख इंवेस्टिगेटर पीटर बेन एम्बार्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमें वहां से बड़े पैमाने पर वायरस के फैलने के संकेत मिले हैं। साथ ही पहली बार इस बारे में भी पता चला है कि दिसंबर 2019 में वुहान में पहले से ही कोरोना के दर्जनों स्ट्रेन मौजूद थे। हम जल्द ही प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करेंगे।

पहले कोरोना मरीज से भी मुलाकात की: डब्ल्यूएचओकी टीम जनवरी में चीन पहुंची थी। टीम ने कोरोना की उत्पत्ति तलाशने के लिए करीब चार हफ्ते तक जांच की और कोरोना की चपेट में आए पहले मरीज से भी मुलाकात की। टीम के मुताबिक, किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रखने वाले 40 साल के व्यक्ति में 8 दिसंबर 2019 को संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

अमेरिका जता चुका है नाराजगी

चीन ने डब्ल्यूएचओ को कोरोना के शुरुआती मामलों से जुड़े आंकड़े देने से भी इंकार कर दिया है। इसके बाद अमेरिका ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। अमेरिका ने कहा था कि उसे डब्ल्यूएचओ की टीम की जांच पर भरोसा नहीं। वह खुद अपने एक्सपर्ट्स की टीम भेजकर मामले की जांच कराएगा।

जल्द आ सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट

टीम इसी हफ्ते अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश कर सकती है। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस अधेनॉम गेब्रेसियस ने बताया कि चीन के वुहान शहर में की जा रही जांच अहम है। हम सभी संभावनाओं को लेकर जांच कर रहे हैं। जल्द ही जांच टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाएगी। इसके कुछ सप्ताह बाद पूरी जांच रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी।

10 करोड़ से ज्यादा मरीज, 23 लाख मौतें

दिसंबर 2019 में वुहान में निमोनिया जैसे लक्षण वाले कुछ मरीजों में नए तरह के कोरोना वायरस की पहचान की गई थी। इसे बाद में कोविड-19 नाम दिया गया। धीरे-धीरे यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए। 23 लाख लोगों की मौत हुई। तब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रम्प ने नए वायरस को चीनी वायरस कहकर इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था।

चीन का विरोध: म्यांमार में चीन की एम्बेसी के सामने प्रदर्शन, शर्म करो चीन और तख्तापलट बंद करो जैसे नारे लगे

यूवांग। म्यांमार में चुनी हुई सरकार के तख्तापलट को 14 दिन बीत चुके हैं। यहां के लोगों में जितना गुस्सा अपने देश की सेना के खिलाफ है, उतना ही चीन के खिलाफ भी। तीन दिन में दूसरी बार यहां चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने- शर्म करो चीन के नारे लगाए। करीब 12 हजार लोगों ने यांगून में चीनी एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि, फौज ने बहुत कम लोगों को एम्बेसी एरिया के पास जाने दिया।

फौज की मदद कर रहा है चीन

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बाद भी स्थानीय लोग यांगून स्थित चीनी दूतावास के सामने बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे। इनमें युवाओं की संख्या ज्यादा थी। कुछ लोगों ने चीनी नागरिकों की तरह मेकअप किया था। ये लोग Shame on you China यानी चीन शर्म करो जैसे नारे लगा रहे थे। पहले तो सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, लेकिन भीड़ बढ़ती देख उन्होंने तय शर्तों के साथ विरोध प्रदर्शन की इजाजत दे दी।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट चीन की सरकार के इशारे पर हुआ है। बीजिंग में बैठी शी जिनपिंग सरकार नहीं चाहती कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार हो। कुछ लोगों ने हाथ में जो पोस्टर लिए थे, उनमें संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का शुक्रिया अदा किया। यूएन, अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन ने तख्तापलट का विरोध किया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने तो मिलिट्री गवर्नमेंट पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं।

साजिश चीन में रची गई

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि म्यांमार में तख्तापलट की साजिश चीन में रची गई और यहां की फौज चीन के इशारे पर काम कर रही है। एक बैनर पर लिखा था- सैन्य शासन चीन की देन। म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन चीन इस पर चुप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को डेली ब्रीफिंग में कहा- हम वहां के हालात पर नजर रख रहे हैं। हमारे उनसे दोस्ताना रिश्ते हैं और हम चाहते हैं कि वहां राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता बनी रहे।

सेना ने तख्तापलट पर क्या कहा था

पिछले साल नवंबर में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थीं। उनकी पार्टी ने लोअर हाउस की 330 में से 258 और अपर हाउस की 168 में से 138 सीटें जीतीं थीं। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही जीतीं। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। इस पार्टी के नेता थान हिते हैं, जो सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं।

नतीजे आने के बाद वहां की सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में सू की की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की शिकायत भी की है। चुनाव नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और वहां की सेना के बीच मतभेद शुरू हो गया। अब म्यांमार की सत्ता पूरी तरह से सेना के हाथ में आ गई है। तख्तापलट के बाद वहां सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया।

जापान में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप

टोक्यो। जापान के फुकुशिमा प्रांत में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मीटियरोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक, इसकी तीव्रता 5.2 रही। एजेंसी ने बताया कि शाम करीब सवा 4 बजे भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 50 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप के बाद सूनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

फुकुशिमा मेंरात भी 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 140 लोग घायल हुए थे। इसके झटके टोक्यो तक महसूस किए गए थे। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कात्सुनोबु कातो ने बताया कि शक्तिशाली भूकंप के कारण देश के 9.50 लाख घरों की बिजली सप्लाई बंद हो गई। भूकंप के बाद, जापानी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक टास्क फोर्स बनाई है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अफसरों से कहा है कि वे नुकसान का जल्द सर्वे करें।

2011 में भूकंप के बाद सूनामी से हुई थीं 16 हजार मौतें

जापान में इसी जगह 10 साल पहले मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप के कारण जबर्दस्त सूनामी आई थी। तब उठी सूनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से

बड़ी घटना माना गया था। तब समुद्र में उठी 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें करीब 16 हजार लोगों की मौत हुई थी।

निकिता जैकब ने जूम मीटिंग की बात कबूली

दिशा रवि व ग्रेटा के वॉट्सऐप चैट से कई खुलासा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज किए गए टूलकिट केस में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहीं वकील कार्यकर्ता निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में दाखिल की गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत अर्जी के साथ दाखिल एक दस्तावेज में निकिता जैकब ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान का उल्लेख किया गया है। बयान में घटनाओं के बारे में विवरण दिया है। उधर, दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच हुई वॉट्सऐप चैट सामने आया है, जिसमें उस पर यूएपीए लगने का डर सता रहा है।टूलकिट मामले से जुड़े पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक 20 से 27 जनवरी के बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी

दी। वकील और कार्यकर्ता निकिता जैकब ने बताया कि 11 जनवरी को पोयटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ जूम कॉल मीटिंग के बारे में लिखा है। उस मीटिंग में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे और होस्ट यानी कि मेजबान ने यह स्पष्ट किया था कि अभियान का कोई राजनीतिक या धार्मिक रंग रूप नही होगा। बातचीत के केंद्र में सिर्फ दिल?ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे थे। होस्ट ने बताया था कि सामग्री सार्वजनिक डोमेन में रहेगी। निकिता ने अपने बयान में कहा कि वो अन्य कई कार्यकर्ताओं की तरह दिल?ली में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों के शांतिपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विरोध के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए शोध और प्रचार कर रही थीं। उनका अपना कोई राजनीतिक, धार्मिक या वित्तीय उद्देश्य नहीं था। निकिता ने यह भी कहा कि उनका आम आदमी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है। ज्ञात हो कि पोयटिक जस्टिस फाउंडेशन का खालिस्तानी आंदोलन से संबंध हैं। इस बीच तीन फरवरी की रात का वो वॉट्सऐप चैट सामने आया है जो दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई बेंगलुरु की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच हुई थी। चैट से खुलासा हुआ कि ग्रेटा ने जब गलती से टूलकिट ट्वीट कर दिया तो दिशा बुरी तरह डर गई।

दिशा को आतंकवाद निरोधक एक्ट यूएपीए का डर सताने लगा

ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर किसान आंदोलन से जुड़ा टूलकिट तीन फरवरी को अपलोड किया था, जो बाद में डिलीट कर दिया गया। इसे लेकर उसी रात को दोनों के बीच चैट हुई। 9 बजकर 23 मिनट पर दिशा ने मैसेज कर ग्रेटा थनवर्ग को उसकी गलती बताई। इसके दो मिनट बाद रात 9 बजकर 25 मिनट पर ग्रेटा ने दिशा को मैसेज किया। इसमें लिखा कि वास्तव में ये अच्छा होगा कि इसे अब तैयार कर लिया जाए। मुझे इसकी वजह से काफी धमकियां मिलेंगी। वास्तव में ये मामला तूल पकड़ रहा है। जवाब में दिशा गलती का इजहार करते हुए कहती हैं कि मैं ये भेज रही हूं तुम्हें।
दिशा - क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूलकिट को पूरी तरह ट्वीट न करें क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। मैं वकीलों से बात करने वाली हूं। मुझे खेद है, लेकिन उस पर हमारे नाम हैं और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। जब दिशा ने ग्रेटा थनवर्ग से यूएपीए वाली बात कही तो कुछ देर तक ग्रेटा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे दिशा और घबरा गई। चार मिनट बाद यानी रात 9 बजकर 40 मिनट पर दिशा फिर वॉट्सऐप करती है और ग्रेटा से पूछती हैं क्या वो ठीक हैं ग्रेटा थनबर्ग -मुझे कुछ लिखने की जरूरत है। दिशा कहती है कि क्या आप पांच मिनट दे सकती हैं. मैं वकीलों से बात कर रही हूं।

निगम अस्पताल में शुरू हुआ टीकाकरण, निगम कर्मचारियों को लग रहा कोरोना का टीका

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से तिलक नगर स्थित निगम अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया गया था और यहां पर मरीजों को रखा जा रहा था। समय के साथ संक्रमण में आई कमी के बाद अब इस अस्पताल में कोविड वार्ड की जरूरत महसूस नहीं की गई और सरकार ने निगम को यह अस्पताल सौंप दिया है। मंगलवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की महापौर अनामिका ने अस्पताल में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की।
यहां पर निगम अधिकारी व कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही जल्द से जल्द अस्पताल में ओपीडी शुरू करने की तैयारी चल रही है। महापौर ने कहा कि निगम में पैसों की कमी के बावजूद अस्पताल में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
स्वास्थ्य कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन श्याम मिश्रा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 28 फरवरी तक निगम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण कराना है। सभी से अपील है कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि एक मार्च से 50 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के साथ-साथ मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति का टीकाकरण भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का यह पहला अस्पताल है जहां पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा उत्तम नगर स्थित डिस्पेंसरी में भी यह सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जो एहतियात हम पहले बरत रहे थे वह अभी भी हमें बरतना है। जब तक कोरोना संकट पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है तबतक हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

सिटीजन फ्रेंडली सिस्टम विकसित करना चाहती है सरकार - राजनाथ सिंह

नई दिल्ली।

अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भारत पूरी दुनिया के लिए संभावनाओं का देश बन गया है। चाहे रक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, कृषि हो, व्यापार हो या फिर आईटी क्षेत्र, विश्व भारत की एक नई छवि देख रहा है। भारत को लेकर पहले जो धारणा थी, वो बीते कुछ वर्षों में अब बदल चुकी है। ये बात रक्षा संपदा भवन में आयोजित ई-छावनी पोर्टल के लोकार्पण समारोह के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहीं। संचालन सोनम यांगडोल ,अपर महानिदेशक और मयंक द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सामाजिक आर्थिक विकास की भरपूर कोशिश कर रही है। साथ ही शासन प्रणाली व प्रक्रिया में बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार प्रयासरत है। ताकि इज आफ लिविंग और इज आफ डूइंग के माध्यम से सरकार जनता को सुविधा दे सकें। रहने की सुविधा, कुछ करने

चार-पांच माह में इस पोर्टल को तैयार करने में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके लिए रक्षा सचिव, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, रक्षा महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस उम्मीद के साथ इस पोर्टल का लोकार्पण किया जा रहा है, उम्मीद है कि वह उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

की सुविधा लोगों को प्राप्त हो। उन्होंने ई-छावनी पोर्टल के लोकार्पण की सभी अधिकारियों को हार्दिक बधाई दी। मिनिमम गवर्मेंट, मैक्सिम गवर्नेंस माडल का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ई-छावनी पोर्टल अच्छे शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इससे छावनी के निवासियों की काफी समस्याओं का समाधान होगा। लंबे समय तक जन प्रतिनिधि रहने के कारण मैं छावनी के निवासियों की समस्या को भलीभांति समझता हूं। ई-छावनी पोर्टल पर लोग न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं बल्कि समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम, सिटीजन फ्रेंडली बने इस दिशा में हमारी कोशिश जारी है।
लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर न लगाना पड़े और न ही उन्हें समस्या के समाधान के लिए घंटो लाइन में खड़ा होना पड़े। इन सभी संकटों से निजात दिलाने में ई-छावनी पोर्टल एक सराहनीय प्रयास है। अच्छी बात ये है कि मोबाइल व कंप्यूटर दोनों पर इस पोर्टल का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चार-पांच माह में इस पोर्टल को तैयार करने में रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके लिए रक्षा सचिव, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, रक्षा महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस उम्मीद के साथ इस पोर्टल का लोकार्पण किया जा रहा है, उम्मीद है कि वह उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसके लिए समय-समय पर लोगों का फीडबैक भी लिया जाना चाहिए। छावनी में रहने वाले लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के संकल्प के साथ हमे आगे बढ़ने की जरूरत है। इस अवसर पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव अजय कुमार, रक्षा महानिदेशक दीपा बाजवा मौजूद रही।

नजफगढ़ के सुरखपुर गांव में शिकार की तलाश में घूमता दिखा तेंदुआ

नई दिल्ली। 21 दिन होने को हैं,लेकिन अभी तक नजफगढ़ के गांवों व शहर की कालोनियों में घूम रहा तेंदुआ पकड़ा नहीं गया है। तेदुआ रात के समय शिकार की तलाश में घूमता रहता है। कुत्तों के पिल्लों को अपना शिकार बना रहा है। श्याम विहार और मित्रऊं के बाद यह तेंदुआ रविवार की रात सुरखपुर गांव के समीप खेतों में देखा गया। जिसने एक मोटरसाइकिल सवार पर हमला भी किया। गनीमत यह थी कि पीछे से आ रहे एक कार सवार ने तेंदुआ को गाड़ी से धक्का दे दिया। कार सवार गांव तक मोटरसाइकिल सवार के साथ चलता रहा, इसलिए तेंदुआ को हमला करने का मौका नहीं मिला और तेंदुआ खेतों में घुस गया, लेकिन यह तेंदुआ रात के समय सुरखपुर गांव की गलियों में भी घूम रहा है और कुत्तों के पिल्लों को उठाकर खेतों में ले जाकर अपना भोजन बना रहा है।

केजरीवाल सरकार तीन साल में यमुना नदी को साफ करके विश्व में उदाहरण पेश करेगी : सत्येंद्र जैन

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरा होने के अवसर पर कहा कि हम यमुना को आने वाले 3 साल के अन्दर साफ करके विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और दिल्ली वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे।
उन्होंने कहा, ÷जैसे दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिलती है, वैसे अब हम दिल्ली के निवासियों को 24 घंटे पानी भी मुहैया कराएंगे ढ्ढ जब हमने 24 घंटे बिजली का वादा किया था, तब लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन आज दिल्लीवालों को 24 घंटे सस्ते दामों पर बिजली मिल रही है। कोरोना काल के दौरान एक साल जो बर्बाद हुआ है, उससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार द्वारा किया गया यमुना को साफ करने का वादा, हम आने वाले तीन सालों में पूरा करके दिखाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का उपयोग करके हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली के निवासियों के लिए 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रही है, जिसमें 500 चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। पिछले 6 सालों में हमारी सरकार ने प्रदूषण पर बहुत गंभीरता पूर्वक अच्छा काम कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें कोरोना काल के दौरान बिजली फ्री मिल रही थी, उन्हें अभी भी बिजली फ्री मिल रही है और जिन्हें बिजली आधी दर में मिल रही थी, उन्हें अभी भी आधी दर पर मिल रही है। केजरीवाल सरकार अभी भी अपने वादों पर पूरी तरह से कायम और टिकी हुई है। लास्ट बिलिंग साइकिल में दिल्ली के 73 प्रतिशत लोगों के बिजली का बिल शून्य आया है। इसके साथ ही 13.66 लाख लोगों के पानी का बिल शून्य आया है। सब को पेंशन पूरी दी गई। हमने दिल्ली में एक लाख 56 हजार ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी है। केजरीवाल सरकार ने 44 हजार निर्माण कार्य से जुड़े पंजीकृत मजदूरों 10-10 हजार रुपए की मदद दी है।

गैस सिलेंडर के बाद दिल्ली में बढ़े चिकन के भी दाम

नई दिल्ली। दिल्ली में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के बीच दिल्ली में चिकन के दाम भी बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि चिकन की मांग दिल्ली में फिर से बढ़ने लगी है। मांग की तुलना में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गा कम आ रहा है। इस वजह से मुर्गे के दाम में इजाफा होने लगा है। सोमवार को बड़ा मुर्गा 80 रुपये और छोटा मुर्गा 95 रुपये किलो तक बिका। थोक में मुर्गे का दाम बढ़ने की वजह से चिकन का भाव 110 से 115 रुपये के बीच पहुंच गया है।
मुर्गा व्यवसायियों का कहना है कि राजधानी में काफी वक्त से बर्ड फ्लू के किसी नए केस की पुष्टि नहीं हुई है। इस वजह से लोगों के मन से बर्ड फ्लू का डर खत्म हो रहा है और चिकन की मांग बढ़ रही है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में बर्ड फ्लू ने दिल्ली में दस्तक दे दी थी। जिसकी वजह से लोग डर गए थे। लोगों ने चिकन से दूरी बना ली थी। उसकी वजह से मुर्गे का कारोबार प्रभावित हुआ। मुर्गे का दाम 65 रुपये किलो तक गिर गया था। दाम में लगातार गिरावट की वजह से मुर्गा व्यवसायी मायूस होने लगे थे। इस कारोबार में करीब एक महीने तक चली सुस्ती अब खत्म होती दिख रही है। सोमवार को मुर्गे का दाम 80 से 95 रुपये किलो के बीच रहा। छोटा मुर्गा महंगा बिका, जिसका दाम 95 रुपये किलो तक रहा। बड़ा मुर्गा 80 रुपये किलो में बिका।

तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सीएम केजरीवाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक साल पहले लोगों ने मुझे फिर से सेवा करने का मौका दिया।
यह एक कठिन वर्ष होने के बावजूद, हमने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मिलकर काम किया। सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों को पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकम्पोजर को दिया। इससे पराली उनके खेत में ही गलकर खाद बन गई। दरअसल, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने छह साल का कार्यकाल मंगलवार को यानी 16 फरवरी को पूरा कर लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह लगातार तीसरा कार्यकाल है। बता दें कि दिल्ली में अरविंद

परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए सरकार ने खजाना खोला। कई विकास कार्य रुके, लेकिन लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। सरकार की तीसरी पारी का पहला साल कोरोना से जूझने में बीता–अकेले भी और केंद्र के साथ मिलकर भी।

केजरीवाल सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल 16 फरवरी पूरा हो रहा है। हालात कुछ ऐसे बने कि तीसरी पारी शुरू करते ही कोरोना की महामारी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। चुनौती अभूतपूर्व थी, स्थितियां डरा रहीं थीं, असमंजस बढ़ रहा था, लेकिन देश के साथ दिल्ली भी जीती। सरकार की पूरी मशीनरी कोरोना पर काबू पाने में जुटी। परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए सरकार ने खजाना खोला। कई विकास कार्य रुके, लेकिन लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। सरकार की तीसरी पारी का पहला साल कोरोना से जूझने में बीता-अकेले भी और केंद्र के साथ मिलकर भी। संक्रमण नियंत्रित हुआ तो अर्थव्यवस्था और विकास को पटरी पर लाने की दिशा में काम शुरू हुआ। दो फ्लाईओवरों और दो अस्पतालों का उद्घाटन किया गया और राशन की डोर स्टेप डिलीवरी व दिल्लीवासियों को हेल्थ कार्ड जारी करने की योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं भी की गईं। ये महत्वाकांक्षी योजनाएं गहरा असर डाल सकती हैं।

सुविधाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाने पर जोर : कैलाश गहलोत

नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार की कोशिश अधिक से अधिक सुविधाओं को नागरिकों के दरवाजे तक मुहैया कराया जाए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 300 से अधिक सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। परिवहन व्यवस्था से जुड़ी सुविधाएं भी जल्द ऑनलाइन कर दी जाएंगी।
वह आइटीओ स्थित दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय में तैयार नए सूचना केंद्र व सेमिनार हाल का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयोग को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आयोग के सूचना केंद्र पर विधि विशेषज्ञों व वालंटियर्स की तैनाती पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इससे निश्चित ही आम लोगों को सहूलियत होगी। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार दोगुनी रफ्तार से आयोग की मदद के लिए आगे बढ़ेगी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान ने कहा कि बजट की बेड़ियां आयोग की रफ्तार रोक दे रही हैं। इस कारण इसके दैनिक कामकाज में भी बाधा आ रही है। इस दिशा में दिल्ली सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नया सूचना केंद्र लोगों की हर तरीके से मदद करेगा। इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने में मदद की जाएगी। इस अवसर पर प्रिंसिपल सचिव (राजस्व) संजीव खेरवाल ने सुझाव देते हुए कहा कि आयोग को अपनी मौजूदगी आनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ताकि लोगों को घर बैठे शिकायतें दर्ज कराने या सुविधाएं उठाने में आसानी हो। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के सचिव मुहम्मद ए. आबिद, आयोग के सदस्य अजीतपाल सिंह बिंद्रा व नैंसी बार्लो समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

कोरोना के संकट के समय भी चलती रही सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सियासत

नई दिल्ली। नगर निगमों के बकाये फंड को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच सियासत एक साल से सुर्खियों में रही है। इस मामले में दोनों पार्टियों के अपने-अपने दावे हैं, आरोप-प्रत्यारोप हैं। भाजपा आप सरकार पर नगर निगमों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाती रही है। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार निगमों को बकाया फंड नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर आप सरकार का कहना है कि नगर निगमों की वित्तीय स्थिति खराब होने के लिए खुद भाजपा जिम्मेदार है। आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने तक पहुंच गया।

भाजपा शासित तीनों नगर निगमों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के लिए स्वास्थ्य व सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का सिलसिला नहीं टूट रहा है। कुछ दिनों पहले भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। फंड के लिए निगमों के महापौर ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर 13 दिनों तक धरना दिया था। भाजपा नेता व कार्यकर्ता दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जगह-जगह पोस्टर-बैनर भी लगाए गए थे।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की राजनीतिक दुर्भावना की वजह से नगर निगमों की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। सरकार फंड जारी करने में नियमों का पालन नहीं कर रही है। दावा किया कि लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही शुरू होने पर भी निगमों को आवंटित फंड का सिर्फ 30 फीसद ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है।

दिल्ली सरकार के मंत्री और आप के प्रदेश संयोजक गोपाल राय का कहना है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। यहां तक कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन के लिए दी जाने वाली राशि भी निगम के भाजपा नेता उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। कर्मचारियों को कई माह तक वेतन नहीं मिलता है। मजबूरन कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। आरोप लगाया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कागजों में गड़बड़ी करके घोटाला किया है। अपने वेतन से पैसे कटवाने के बाद भी सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा के लिए भटक रहे हैं।

गोपाल राय का कहना है कि आखिर कर्मचारियों के वेतन से काटे गए पैसे किसकी जेब में गए हैं, इसकी जांच जरूरी है। भ्रष्टाचार की वजह से लोगों के जरूरी काम नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे-छोटे काम के लिए भी निगम में पैसे मांगे जा रहे हैं।

अकेली लड़की को देख मोबाइल स्नैचरों ने किया अटैक

नई दिल्ली। लड़की को आसान शिकार समझकर झपटमारों ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया और स्कूटी से भागने लगे। झपटमारों की एकाएक हरकत का लड़की ने फौरन जवाब दिया और शोर मचाने लगी। लड़की ने स्कूटी के पीछे बैठे झपटमार का हाथ पकड़ लिया। झमटमार ने लाख कोशिश की लेकिन लड़की ने हाथ नहीं छोड़ा। दूसरे बदमाश ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ाकर मौके से भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अंत में संतुलन गड़बड़ाने से स्कूटी पर सवार दोनों झपटमार नीचे गिर गए। इस बीच आसपास मौजूद लोगों ने दोनों झपटमारों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब पुलिस अधिकारी लड़की के हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। तिलक नगर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में इस लड़की ने कहा है कि वे 11वीं कक्षा में पढ़ती हैं। 15 फरवरी को शाम करीब छह बजे ये अपनी सहेली के घर किताब के लिए आई थीं। सहेली से किताब लेने के बाद ये बस पकड़ने के लिए बाहरी रिंग रोड की ओर पैदल जा रही थीं। जब ये सर्विस रोड से गुजर रही थीं तभी पीछे से एक सफेद रंग की स्कूटी आई और इनके हाथ से मोबाइल फोन झपट्टा मारकर छीन लिया और भागने लगे। जब ये भाग रहे थे तभी पीछे बैठे झपटमार का हाथ इन्होंने पकड़ा और उसे खींचने लगी। इससे स्कूटी चला रहे शख्स क संतुलन बिगड़ा और स्कूटी नीचे गिर गई। तब तक आसपास मौजूद लोग भी लड़की द्वारा मचाए शोर सुनकर पहुंचे। सारी बात समझने के बाद लोगों ने दोनों झपटमारों को पकड़ लिया। इस बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने दोनो लड़के सौंप दिए। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो आरोपितों ने अपना नाम भूपेश व हर्ष बताया। छानबीन में पता चला कि आरोपित जिस स्कूटी पर सवार थे वह तिलक नगर इलाके से चुराई गई थी। मामले की तहकीकात जारी है।

शिक्षा के मानव संसाधन मॉडल ने विद्यार्थियों को टूल बनाने का काम किया : मनीष सिसोदिया

नई दिल्ली। भारतीय विश्वविद्यालय संघ, उत्तरी जोन द्वारा गुरुगोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय वर्चुअल उपकुलपति संवाद कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के सलाह से बने शिक्षा मंत्रालय का स्वागत करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति ने यह मान लिया कि शिक्षा का काम केवल मानव को संसाधन मात्र बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि अबतक भारत का शिक्षा मॉडल बच्चों को एक संसाधन के रूप में ढाल रहा था, उन्हें टूल के रूप में तैयार कर रहा था, जबकि शिक्षा का असल उद्देश्य बच्चों को एक अच्छा मानव और नागरिक बनाना है, संसाधन नही। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्तमान में उच्च शिक्षा के 4 चुनौतियों पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत के विश्वविद्यालयों के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती

विस्तार करने की है। पिछले बीस सालों में भारत में स्कूलों से बड़ी संख्या में बच्चे पास होकर निकल रहे है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों के पास उन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों के विस्तार की जरूरत है। सिसोदिया ने कहा कि देश में आजादी के बाद शिक्षा पर कार्य हुए, लेकिन उसका लाभ सिर्फ 5 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही मिला, जबकि शेष 95 प्रतिशत बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। सरकारों की नीतियां और प्राथमिकताएं चाहे जो भी रही हों, लेकिन आउटकम पर नजर डालें तो यही दिखेगा कि 95 प्रतिशत बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह गए। इसलिए आज यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम शिक्षा का एक न्यूनतम मानदंड जरूर तय करें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज हमारे विश्वविद्यालयों के सामने अपनी पहचान बनाए रखने की चुनौती है। अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुसंधानों एवं नवाचारों पर काम करने की आवश्यकता है। अपने पाठ्यक्रमों में उद्यमिता को शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को यह समझना होगा कि उनका भूतकाल उनका भविष्य नहीं बन सकता। भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों को अपने ढाँचे में बदलाव लाना होगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज भारत से ब्रेन-ड्रेन हो रहा है। हम भारत की प्रतिभाओं को विदेशी कंपनियों को दान दे रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के देश विकासशील देशों की प्रतिभाओं को ढूंढ कर अपने देशों में ले जाते है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे विद्यार्थी उन देशों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने में तो कामयाब हो रहे है, पर राष्ट्र निर्माण में उन प्रतिभाओं को शामिल करने में विफल रहे हैं।

संपादकीय

आने को है रुपहले परदे पर बहार

पिछले साल 20 मार्च को नोएडा के एक मल्टीप्लेक्स में देर शाम के शो में नई रिलीज हुई इंग्लिश मीडियम देखने मुट्ठी भर दर्शक पहुंचे थे। दुनिया में कोविड महामारी पैर पसारने लगी थी। हमारे यहां भी सब सजग हो रहे थे। मैं भी पशोपेश में थी, लेकिन इरफान खान को बड़े परदे पर देखने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। फिल्म देखकर खाली सिनेमा हॉल से निकलते समय अजीब सा एहसास हुआ, इतना सन्नाटा पहले तो कभी नहीं था। उस वक्त यह अंदाज नहीं था कि इंग्लिश मीडियम के बाद लंबे समय तक कोई और फिल्म थियेटर में रिलीज नहीं होगी। हम जैसे फिल्मों के शौकीन जो हर सप्ताह किसी नई और अच्छी फिल्म का इंतजार करते हैं, उनके लिए टीवी, लैपटॉप या टैबलेट का कुछ इंची परदा एक समझौते की तरह है। यह सच है कि लगभग पूरे साल ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन का भरपूर डोज दिया, पर क्या इससे वह संतुष्टि मिली, जो बड़े परदे पर एक शाहकार फिल्म देखने के बाद होती है? नहीं, कतई नहीं। दोनों अनुभव अलग-अलग हैं। रुपहले परदे के जादू का कोई विकल्प नहीं है।

अक्तूबर में सरकार ने सशर्त पचास प्रतिशत क्षमता के साथ फिल्म थियेटर खोलने की अनुमति दे दी थी। उस समय हमारे देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही थी। साल 2020 की बड़ी फिल्में सूर्यवंशी और 83 के प्रदर्शन की तारीखें लगातार टल रही थीं। जाहिर था कि निर्माता इन बड़ी फिल्मों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे। साल के अंत में जो फिल्में थियेटर में आईं भी, वे छोटी फिल्में थीं। साथ ही, वे तुरंत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आ गईं। थियेटर में फिल्म देखने बेहद कम लोग पहुंचे। फरवरी की पहली तारीख से सरकार ने देश भर में फिल्म थियेटरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया है। अप्रैल की दो तारीख को साल की सबसे बड़ी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज होने जा रही है। अक्षय कुमार की यह फिल्म पिछले साल से रुपहले परदे पर आने का मुंह ताक रही है। हालांकि, यह फिल्म साल की दूसरी तिमाही में आएगी, पर माना जा रहा है कि इस फिल्म के साथ दर्शक थियेटरों में दोबारा लौटेंगे। देश में कोरोना के मरीजों की घटती संख्या, टीकाकरण आदि की खबरों की वजह से भी एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। हम हिन्दुस्तानियों के डीएनए में क्रिकेट और फिल्में रची-बसी हैं। हम इनसे ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकते। ट्रेड पंडित और फिल्म क्रिटिक जोगेंदर टुटेजा कहते हैं, 'पिछले साल इंडस्ट्री को लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अगर इस साल स्थिति सुधरेगी, तब भी हम लगभग दो हजार करोड़ रुपये के नुकसान में रहेंगे।' इंडस्ट्री से जुड़े एक्जीबीटर, विश्लेषकों और निर्माताओं का मानना है कि दर्शक फिल्म थियेटर में वापस आने को बेताब हैं। आप पहले की तरह उन्हें बड़ी फिल्में दीजिए, वही माहौल दीजिए। पिछले महीने दक्षिण भारत में दो बड़ी फिल्में मास्टर और क्रेक बड़े परदे पर आईं। मास्टर ने महज एक सप्ताह में 175 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। थियेटरों में पचास प्रतिशत दर्शकों के बावजूद ये आंकड़े संतोषजनक रहे, लेकिन फिल्म रिलीज होने के मात्र 16 दिन बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई। इस वजह से थियेटर में दर्शकों की संख्या पर असर पड़ गया। इस समय बॉलीवुड भी इस विवाद में उलझा हुआ है कि थियेटर में आने के बाद कम से कम छह सप्ताह बाद ही ओटीटी पर फिल्में आनी चाहिए, ताकि निर्माता, फाइनेंसर और थियेटर मालिकों को भी मुनाफा मिल सके। सूर्यवंशी के साथ भी यह दिक्कत सामने आ रही है। इस फिल्म की रिलीज को साल भर टालने की वजह से फिल्म की कीमत में पंद्रह से बीस प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है। अगर इसके साथ यह डर या भ्रम बना रहे कि रिलीज के चंद सप्ताह बाद ही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, तो इससे सिनेमा हॉल वाली सफलता पर काफी असर पड़ सकता है।

पिछले साल बॉलीवुड की कमाई न्यूनतम रही और नुकसान तगड़ा हुआ। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई और बोनी कपूर की फिल्म मैदान का करोड़ों का सेट बनकर तैयार था, लेकिन कोविड की वजह से शूटिंग को रोक दिया गया। लॉकडाउन का समय बढ़ता गया, दोनों फिल्मों के आलीशान सेट को ढहा देना पड़ा। शूटिंग शुरू होने के बाद दोबारा ये दोनों सेट बने। इससे फिल्म का बजट भी बढ़ गया और इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान का आंकड़ा भी। इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। बॉलीवुड ट्रेड विशेषज्ञ कोमल नाहटा की मानें, तो अगर हम पिछले साल से लेकर आने वाले कुछ साल तक फिल्म उद्योग के नुकसान का आकलन करें, तो यह नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैठेगा। हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हम बड़ी और अच्छी फिल्में बनाएं और दर्शकों को बड़े परदे पर लौटने की दावत दें। पिछले साल बॉलीवुड को जो तगड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आने वाले दो सालों तक नहीं हो सकती। बॉलीवुड छह साल पीछे चला गया है। इस उद्योग से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस साल अप्रैल के बाद मई में ईद के समय सलमान खान की फिल्म राधे ञ युअर मोस्ट वांटेड भाई आएगी। उसी दौरान जॉन अब्राहम की देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी रिलीज होगी। जून में रनवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित खेल फिल्म 83 आएगी। 13 अक्तूबर को उत्सवों का आगाज करेंगी बाहुबली के निर्देशक राजमौली की त्रिभाषी फिल्म आरआरआर और बोनी कपूर की बड़ी फिल्म मैदान। नवरात्र और दिवाली का वक्त किसी भी फिल्म की रिलीज के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए उस सप्ताह अगर दो बड़ी फिल्में भी आएंगी, तो उन्हें दर्शकों की कमी नहीं होगी। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा लेकर आ रहे हैं। गौरतलब है कि सिर्फ इस साल के ही नहीं, अगले साल के भी सभी महत्वपूर्ण दिन जैसे वेलेंटाइन, होली, गरमी की छुट्टियां, ईद, दिवाली और क्रिसमस पर बड़ी फिल्मों ने अभी से अपने नाम की मुहर लगा दी है।

प्रवीण कुमार सिंह

मोदी सरकार को विपक्ष के नकारात्मक और उद्योग विरोधी माहौल की अनदेखी कर बड़े सुधारों की ओर बढ़ना चाहिए

> सरकार विपक्ष के नकारात्मक माहौल की अनदेखी कर सुधारों की ओर बढ़े अच्छा होगा कि सरकार विपक्ष की ओर से बनाए जा रहे नकारात्मक माहौल की अनदेखी कर सुधारों की ओर बढ़े और यह ध्यान रखे कि सुधार तभी कारगार होंगे, जब उन्हें लेकर जनता के बीच व्यापक चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों के मामले में यह काम किसानों के बीच किया जाना चाहिए था। कोई भी बड़ा बदलाव कुछ समस्याएं खड़ी करता है, लेकिन आम जनता तकलीफ सहने को तभी तैयार होगी, जब बड़े सुधारों के मामले में सरकार उसे भरोसे में लेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट एक फरवरी को आ रहा है। इस बजट की ओर लोगों की निगाहें इसलिए अधिक हैं, क्योंकि यह तब आ रहा, जब भारत महामारी कोविड-19 से निपटने में लगा हुआ है। इस महामारी के चलते भारत में करीब चार महीने लॉकडाउन रहा। इस कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, लेकिन जैसा कि अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि उसमें तेज उछाल आएगी, वैसा ही हो रहा है। उम्मीद है बजट में उस नुकसान की भरपाई के विशेष प्रविधान किए जाएंगे, जो कोरोना काल में हुआ। सरकार को यह देखना होगा कि उसका घाटा भी नियंत्रित रहे और सामाजिक योजनाओं के लिए धन की कमी भी न हो। अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स की दरें असामान्य रूप से नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। ऊंची टैक्स दरें काली कमाई को बढ़ावा देती हैं। बेहतर होगा कि सरकार कोविड काल में हुए घाटे को यथासंभव वहन करे और ज्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने पर दे। यह अच्छा है कि आर्थिक सर्वे में खर्च बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह अपना हाथ उन तमाम उद्योगों से खींचे, जिन्हें वह अभी भी चला रही है। सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की प्रक्रिया को गति दी जानी चाहिए, क्योंकि मुक्त बाजार के दौर में इसका औचित्य नहीं कि सरकार खुद उद्योग चलाए। उसका काम तो उद्योगों के संचालन के तौर-तरीके तय करने और उनकी निगरानी तक सीमित रहना चाहिए। यह विडंबना है कि एक के बाद एक सरकारें विनिवेश की बात तो करती रहीं, लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों से हाथ खींचने से बचती भी रहीं। इसी का नतीजा है कि सरकार एयर इंडिया जैसे उपक्रम चला रही है। इसी तरह अन्य अनेक उपक्रम केंद्र या राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं।

आम बजट ऐसे समय आ रहा है, जब कृषि कानूनों को लेकर धरना-प्रदर्शन जारी है। आम किसानों को इन कानूनों से कोई परेशानी नहीं, मगर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। इसी कारण गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जगह-जगह जो उपद्रव हुआ और यहां तक कि लाल किले पर भी उत्पात मचाया गया, उसके कारण किसान आंदोलन बहुत बदनाम हुआ। इस बदनामी के बाद भी वे अड़ियल रवैया दिखा रहे हैं। वे कृषि कानूनों को लेकर खुद भी भ्रमित हैं और किसानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। चूंकि कोरोना काल में कृषि ने देश को बड़ा सहारा दिया इसलिए यह ठीक ही है कि आर्थिक सर्वे में कृषि और किसानों के लिए खास उपाय करने के संकेत दिए गए। सरकार को बजट में ऐसे उपाय करके राजनीतिक लाभ लेने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि अफवाह आधारित किसान आंदोलन की धार कुंद हो।

कृषि के अलावा दो और क्षेत्र हैं, जो इस समय विशेष मांग कर रहे हैं- एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या में कमी दिखी। अब जब महामारियां आते रहने का अंदेशा बढ़ गया है तब स्वास्थ्य संबंधी ढांचे की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे भी यह कहता है कि स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर भी खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। कोरोना काल में पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित हुआ। छात्रों को जिस तरह घर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ी, वह उनके लिए अप्रत्याशित अनुभव रहा। पढ़ाई वही जो कक्षा में जाकर की जाए, लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के प्रयोग ने यह संभावना बढ़ा दी है कि बड़ी संख्या में छात्रों को इसी तरह शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वैसे सरकार ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट पहुंचा रही है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा संतोषजनक नहीं।

सरकार को इंटरनेट ढांचे को और व्यापक करना चाहिए, ताकि डिजिटल इंडिया मुहिम को बल मिले। यह सही है कि नई शिक्षा नीति पर अमल शुरू हो गया है, लेकिन उसे पूरी तरह लागू करने के लिए अच्छे-खासे बजट की आवश्यकता है। देखना है कि बजट में इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होती है? इस समय अर्थव्यवस्था शहरों से चल रही है, लेकिन उनका आधारभूत ढांचा चरमराता जा रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी योजना के जरिये शहरों के आधारभूत ढांचे को ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उन्हें अनियोजित विकास से बचाना आसान नहीं। मेट्रो सेवा शुरू करने या ओवरब्रिज बनाने से ही समस्या का निवारण नहीं होगा। शहरों को बेहतर बनाने के लिए बड़े बजट के साथ ही राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिकों के सहयोग की भी आवश्यकता है।

बजट सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके यह साफ कर दिया कि वे सरकार को सहयोग नहीं देंगे। विपक्ष का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को उद्योगपतियों की सरकार बताकर उद्यमशीलता पर जानबूझकर चोट कर रहे हैं। कांग्रेस का मुक्त बाजार विरोधी रवैया यही बताता है कि वह वामपंथी अतिवाद से ग्रस्त हो रही है। वह पहले भी इसी रवैये से ग्रस्त रही और इसी कारण देश वैसी तरक्की नहीं कर सका, जैसी अन्य देश कर गए। यह तो गनीमत रही कि जिस वक्त नरसिंह राव सरकार ने अर्थव्यवस्था खोलने का काम किया, उस समय कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार के पास नहीं था, अन्यथा देश की और दुर्दशा होती।

कांग्रेस की देखा-देखी अन्य विपक्षी दलों पर भी वामपंथी अतिवाद हावी हो रहा है। वे मुक्त अर्थव्यवस्था के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाकर यह संदेश दे रहे हैं कि लोगों को खुशहाली सिर्फ सरकार दे सकती है। यह लोकलुभावन सोच उद्यमशीलता पर सीधी चोट है। विपक्ष के दुष्प्रचार और दबाव में आकर मोदी सरकार को बड़े सुधारों से हिचकिचाना नहीं चाहिए। सरकार विपक्ष के नकारात्मक माहौल की अनदेखी कर सुधारों की ओर बढ़े अच्छा होगा कि सरकार विपक्ष की ओर से बनाए जा रहे नकारात्मक माहौल की अनदेखी कर सुधारों की ओर बढ़े और यह ध्यान रखे कि सुधार तभी कारगार होंगे, जब उन्हें लेकर जनता के बीच व्यापक चर्चा की जाएगी। कृषि कानूनों के मामले में यह काम किसानों के बीच किया जाना चाहिए था। कोई भी बड़ा बदलाव कुछ समस्याएं खड़ी करता है, लेकिन आम जनता तकलीफ सहने को तभी तैयार होगी, जब बड़े सुधारों के मामले में सरकार उसे भरोसे में लेगी।

नैतिकता विहीन राजनीति की नई नीति लंबे समय तक जनता को भ्रमित रखने में नहीं होगी कामयाब

बीते सप्ताह घटित दिल्ली और पटना की दो असंबद्ध बातें आने वाले दिनों में आम जनता पर व्यापक असर डालने वाली हैं। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली में नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं दूसरी ओर बिहार में आर्थिक अपराध शाखा के उपमहानिदेशक द्वारा सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों समेत सांसदों और विधायकों के बारे में इंटरनेट मीडिया में किसी तरह के भ्रामक तथ्य लिखने पर एफआइआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया।

उपरोक्त दोनों घटनाओं पर गौर करने से स्पष्ट होता है कि 21वीं सदी के 21वें साल में नैतिकता विहीन हो चुकी राजनीति में पुरानी नीतियां भी बदल गई हैं। आडंबर के चकाचौंध से लोक सेवा को प्रभावित करने की नई नीति लंबे समय तक जनता को भ्रमित रखने में कामयाब नहीं होगी। इसलिए न्याय के मंदिर ने शासन-प्रशासन में जमे नेताओं को सचेत किया है कि जनता उनकी भी मॉब लिंचिंग सकती है। हालात की भयावहता को दर्शाने के लिए यह कथन अपनेआप में काफी है।

दरअसल दिल्ली में सरकार ही सरकार है। यहां केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच एक अर्से से तनातनी चल रही है। परंतु ये दोनों ही स्थानीय सरकार नहीं हैं। तीसरी सरकार के नाम से प्रचलित नगर निगम पहले तो एनडीएमसी और एमसीडी में ही विभाजित रही, परंतु वर्ष 2012 में एमसीडी को भी तीन हिस्सों में बांटा गया। फिर सत्ता के संघर्ष में दावेदारों की वृद्धि हुई। इसके अलावा, बिना किसी चुनाव प्रक्रिया का सहारा लिए बाबुओं के बूते चलने वाली डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली जल बोर्ड जैसे संगठन भी किसी सरकार से कम नहीं हैं।

केंद्र और राज्य की सरकारों के अधीन कार्यरत होने के बावजूद ये सत्ता के प्रतिष्ठान हैं। महानगर में सफाई, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सेवा के लिए प्रतिबद्ध नगर निगमों में भाजपा का राज है। केंद्र में भी इसी दल की सरकार है। इन दोनों के बीच दिल्ली प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थिति सैंडविच की तरह हो गई है। महानगर की गलियां आजकल इन दोनों ही राजनीतिक दलों के इश्तेहारों से भरी हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

दरअसल शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर लोगों की सेवा को लोकतंत्र का मूलमंत्र माना जाता है। यही शक्ति जब कमजोर को सताने में खर्च होती है तो उसे जंगलराज कहते हैं। ऐसी दशा में मोबोक्रेसी और डेमोक्रेसी का भेद खत्म हो जाता है। दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठानों का समीकरण साधने में व्यस्त लगभग सभी पार्टियां लोक सेवा का कार्य भूल गई हैं।

राजधानी दिल्ली में आज जिस तरह की स्थिति है, उसे नजदीक से देखने पर यह कहा जा सकता है कि यहां सभी स्तरों की सरकारों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। शासन-प्रशासन में ऊंचे स्तर पर जमे नेताओं द्वारा अधीनस्थ लोगों का शोषण कर भष्मासुर होने का प्रमाणपत्र दिया जा रहा है। यदि इस तरह के हालात नहीं सुधरे तो राजनीतिक दलों के दलदल से दूर रहने वाले लोग इस शोषित तबके के साथ मिलकर उस तरह की गतिविधि को भी अंजाम दे सकते हैं, जिस बारे में न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा है।

वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार को अपने ही बयानवीर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को जनता के बीच भ्रामक तथ्यों को परोसने के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई का प्रविधान करना चाहिए। राज्य में थानों की पुलिस अब लोगों को इंटरनेट मीडिया चलाने का सलीका सिखा रही है और आइपीसी की धारा 409, 420 और 467 के अलावा आइटी एक्ट की धारा 64, 65 और 67 का पाठ पढ़ा रही है। लेकिन इसका जमकर विरोध होने लगा। परिणामस्वरूप अगले ही दिन रचनात्मक आलोचना को छूट देने की बात भी कही गई।

समग्रता में देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की यह कोशिश वस्तुत- सरकार की कमजोरी का ही द्योतक है। अफवाहों का व्यापार, गलत बयानबाजी और नफरत की आवाजों पर रोक लगे तो देश का हित होगा। बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री हाल ही में राज्य में एक एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़े मामले में गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए पाए गए हैं। लिहाजा इस क्रम में इन तथ्यों की जांच कराते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सरकार एक नजीर भी पेश कर सकती है। ऐसा नहीं करने पर सुशासन हास्य व्यंग्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं साबित होगा। यह न ही अच्छे वर्तमान की निशानी है और न ही बेहतर भविष्य का सूचक।

आखिर बनी सहमति

महीनों चले गतिरोध के बाद आखिर भारत-चीन सीमा पर आमने-सामने तैनात सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में दोनों पक्षों के बीच इस बारे में बनी सहमति की घोषणा की। बीते जून में गलवान घाटी में हुई भिड़ंत के बाद से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में जिस तरह का संदेह और अविश्वास घर कर गया है, उसके दूर होने में तो समय लगेगा लेकिन पैंगोंग झील के पास से दोनों सेनाओं का अपने-अपने स्थान से पीछे हटना यकीनन एक अच्छी शुरुआत है।

खासकर इसलिए भी कि जैसा रक्षामंत्री ने संसद में बताया, सहमति अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस जाने को लेकर बनी है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर चीनी सैनिक फिंगर 8 के पास रहेंगे और भारतीय सैनिक फिंगर 3 के पास। अप्रैल से पहले तक भारतीय टुकड़ियां फिंगर 8 तक गश्त लगाती थीं, लेकिन अभी फिंगर 3 से 8 के बीच गश्त लगाने पर अस्थायी रोक रहेगी। तनाव के दौरान इस क्षेत्र में जो निर्माण किए गए हैं, उन्हें हटाए जाने की बात भी खासी महत्वपूर्ण है।

हालांकि इस पहलू को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह समझौता सिर्फ एक विवादित क्षेत्र को लेकर हुआ है। उत्तर में डेपसॉन्ग मैदान और दक्षिण में गलवान घाटी समेत विवाद के बाकी बिंदुओं पर फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। राजनाथ सिंह ने भी अपने बयान में इस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि विवाद के कई बिंदु अभी पेंडिंग हैं। फिर भी जितनी सहमति बनी है उसकी अहमियत कई बिंदुओं पर विवाद बचे रह जाने के कारण कम नहीं हो जाती। इससे यह उम्मीद तो जगी है कि दोनों पक्ष थोड़ी समझदारी दिखाएं तो विवादों के बीच भी तनाव कम करने की राह निकाली जा सकती है। सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे सीमा पर कभी भी कुछ भी हो जाने का डर कम होता है, खजाने पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ घटता है और एक साथ दो-दो सीमाओं पर युद्ध की आशंका के बीच जीने की मजबूरी खत्म होती है।

दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को स्थायी तौर पर हल करने का लक्ष्य काफी दूर है, लेकिन अगर परस्पर विश्वास के साथ एक-दूसरे के दावों और वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करते हुए बातचीत जारी रखें तो सहयोगपूर्ण रिश्ते उसी तरह जारी रह सकते हैं, जैसे पिछले तीन दशकों से बने हुए थे। चीन की हालिया हरकतों से आपसी विश्वास की बुनियाद में दरार पड़ गई है लेकिन कोशिश की जाए तो यहां से भी हालात संभाले जा सकते हैं।

पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को लेकर बनी इस सहमति पर सही ढंग से अमल सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि यह अन्य क्षेत्रों में भी सहमति कायम करने का आधार बन सके।

देश में कोरोना के मोर्चे पर हालात सुधरने के बावजूद राहुल पीएम मोदी पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं

> ऐसे में यह बहुत दुखद है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता इस वास्तविकता को समझने में नाकाम रहे और अपने छिछले आरोपों से लगातार केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही उन स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा और समर्पण पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना मरीजों का उपचार किया। यह विध्वंसकारी राजनीति का चरम है। सौभाग्य से उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ समझदार नेता हैं जो उनकी राय से सहमति नहीं रखते और देश को इस भयंकर संकट से बाहर निकालने में अनर्थक प्रयास कर रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस घेब्रेयसिस ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। हाल में उन्होंने कहा कि एकजुट होकर ही हम इस आपदा से लोगों का जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकते हैं। दरअसल डब्ल्यूएचओ के मुखिया भारत द्वारा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल जैसे तमाम पड़ोसी देशों को वैक्सीन आपूर्ति करने के फैसले के आलोक में यह प्रशंसा कर रहे थे। पिछले एक वर्ष में यह चौथा अवसर था जब डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने केंद्र सरकार द्वारा महामारी से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की सराहना की।

गत वर्ष जुलाई में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली धारावी (मुंबई) में कोरोना संक्रमण को रोकने की तारीफ की थी। इसे मिसाल बताते हुए उन्होंने कहा था कि यह दर्शाता है कि चरम पर होने के बावजूद संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है। गत वर्ष उन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की प्रशंसा की थी जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत वैक्सीन के मोर्चे पर अपनी शक्ति का उपयोग वैश्विक समुदाय को कोरोना से मुक्ति दिलाने में करेगा। फिर नवंबर में जब पीएम मोदी ने घेब्रेयसस से वार्ता की तो डब्ल्यूएचओ के सर्वेसर्वा ने भारत के प्रयासों और आयुष्मान भारत जैसी पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गत वर्ष मई में भारत में डब्ल्यूएचओ प्रतिनिधि ने भारत के प्रयासों को व्यापक एवं प्रभावी बताया था। इस संस्था ने उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन विशेषकर कांटैक्ट-ट्रेंसग रणनीति की तारीफ करते हुए कहा था कि यह अन्य राज्यों द्वारा अपनाने योग्य भी है।

अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को अपने प्रयासों पर खूब वाहवाही मिली। अमेरिका ने भी डब्ल्यूएचओ के सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि भारत दूसरे देशों की वैक्सीन जरूरतें पूरी करने के लिए तत्पर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, 'हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका को सराहते हैं जो दक्षिण एशिया में कोविड टीके की लाखों खुराक साझा कर रहा है।'

आखिर इन बातों के क्या मायने हैं? दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण हैं ताकि नागरिकों को कुछ नेताओं विशेषकर राहुल गांधी द्वारा कोविड प्रबंधन के मामले में लगातार किए जा रहे दुष्प्रचार और नकारात्मकता से मुक्ति मिले। यह तब है जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देश कोरोना से निपटने में अभी भी लड़खड़ा रहे हैं वहीं भारत में केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों में विभिन्न दलों के नेतृत्व वाली सरकारों ने कदम से कदम मिलाकर सेहत संबंधी उस आपदा से निपटने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जैसी आपदा से देश सदियों में एक बार ही दो-चार हुआ हो।

राहुल गांधी ने पहले तो गत वर्ष मार्च में मोदी सरकार द्वारा लगाए लॉकडाउन की आलोचना की और जब सरकार ने लॉकडाउन हटाया तो उन्होंने उसका भी विरोध किया। अपनी दलीलों को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के आंकड़ों का उदाहरण दिया जहां लॉकडाउन हटाने के बाद कोरोना मामले घटे जबकि भारत में उनमें तेजी आई। उसके बाद से ही वह कोविड से निपटने में देश के प्रयासों की आलोचना करते आए हैं। इसमें उन्होंने यह लिहाज भी नहीं किया इस पर उनके द्वारा की जा रही क्षुद्र राजनीति देश की छवि ही खराब कर रही है। अब उन देशों की खस्ताहालत को देखते हुए पता नहीं उनके पास क्या तर्क होंगे? चूंकि वहां कोविड-19 काबू से बाहर हो रहा है तो ये देश नए सिरे से लॉकडाउन लगाने पर विवश हैं।

दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक लोग अब तक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारत में 24 जनवरी को कोरोना के 13,203 नए मामले सामने आए, जो 14 सितंबर 2020 को आए 97,894 के चरम पर पहुंचे मामलों से खासे कम हैं। गत चार महीनों से नए मामलों में कमी आ रही है। इसके उलट राहुल जिन देशों की तारीफों के पुल बांध रहे थे वे देश फिलहाल भारी मुश्किल में फंसे हैं। इस समय ब्रिटेन में 20 लाख तो फ्रांस में 27 लाख सक्रिय मामले हैं जबकि भारत में 1.78 लाख ही सक्रिय मामले रह गए हैं। वहीं 2.5 करोड़ मामले दर्ज करने वाले अमेरिका में अभी भी करीब एक करोड़ सक्रिय मामले हैं। ऐसे में यह अजीब लगता है कि भारत में हालात सुधरने के बावजूद राहुल गांधी मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाकर हमला करने में लगे हैं। उनका आरोप है कि अनियोजित लॉकडाउन जैसे कदम से हालात बेकाबू हो गए और लाखों लोग मर गए। इसके उलट सत्य यही है कि भारत उन देशों में से एक है जहां इस महामारी के चलते मृत्यु दर खासी कम रही। एक करोड़ संक्रमितों में से यहां 1.5 लाख लोगों की जान गई। यानी मृत्यु दर 1.5 फीसद रही जो दुनिया में न्यूनतम दरों में से एक है। अच्छी बात यही है कि अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। वे केंद्र के सक्रिय सहयोग से अपने राज्यों में इस संकट का समाधान करने में जुटे हैं।

इस बीच डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम की स्वतंत्र निगरानी एवं सलाहकार समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में महामारी से निपटने के उपायों पर हो रही राजनीति की आलोचना की है। यह रिपोर्ट राहुल गांधी जैसे नेताओं की ओर ही इशारा करती है जिसमें कहा गया है कि सरकारों पर ऐसे आरोपों से जनता का मनोबल गिरता है और इस अभियान को ठेस पहुंचती है। समिति का यही मानना है कि इस अप्रत्याशित संकट में दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है और व्यापक वैश्विक एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग के बिना इसे मात दे पाना मुश्किल है।

ऐसे में यह बहुत दुखद है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता इस वास्तविकता को समझने में नाकाम रहे और अपने छिछले आरोपों से लगातार केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही उन स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा और समर्पण पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना मरीजों का उपचार किया। यह विध्वंसकारी राजनीति का चरम है। सौभाग्य से उनकी अपनी ही पार्टी में कुछ समझदार नेता हैं जो उनकी राय से सहमति नहीं रखते और देश को इस भयंकर संकट से बाहर निकालने में अनर्थक प्रयास कर रहे हैं।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

औरैया में ट्रक से टकरा कार पलटने से चार की मौत, बेटी का रिश्ता तय करने कानपुर जा रहा था परिवार

औरैया । आगरा से कानपुर बेटी का रिश्ता तय करने जा रहा परिवार औरैया में मंगलवार की सुबह हादसे का शिकार हो गया। हाईवे पर करमपुर के पास ट्रक में पीछे से टकराकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार दंपती, बेटी और उसके मामा की मौत हो गई, जबकि भाई घायल हुआ है। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराकर कार्रवाई शुरू की है।

आगरा के बालेश्वर मोहल्ला निवासी राजकुमार ने बेटी दीक्षा की शादी के लिए कानपुर में बात शुरू की थी। वर पक्ष को बेटी दिखाने के लिए मंगलवार का दिन तय हुआ था। 53 वर्षीय राजकुमार मंगलवार को 50 वर्षीय पत्नी भावना, 27 वर्षीय बेटी दीक्षा, 25 वर्षीय बेटे रजित और 51 वर्षीय साले महावीर को लेकर कानपुर के लिए कार से निकले थे। कार को बेटा रजित चला रहा था। सुबह करीब आठ बजे औरैया में हाईवे पर करमपुर मोड़ के पास आगे चल रहे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार कई बार हाईवे पर पलटी खा गई, जिससे उसके परखचे उड़ गए। हादसे में कार सवार दंपती, बेटी व मामा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रजित घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं हाईवे की एक लेन पर यातायात बाधित हो गया और ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

सूचना पर सीओ सिटी सुरेंद्रनाथ यादव, सदर कोतवाल संजय पांडेय मौके पर पहुंचे और कार सवार लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहन को किनारे कराकर यातायात बहाल कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि रजित का उपचार शुरू किया। पुलिस की पूछताछ में रजित ने पूरी जानकारी दी। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। बहन की शादी धूमधाम से कराने के सपने चंद पल में चकनाचूर हो गए। जिला अस्पताल में रजित रोते-रोते बार-बार एक ही बात पूछ रहा था कि उसके माता-पिता, बहन व मामा कैसे हैं। अभी उसे ये भी पता नहीं था कि उसी दुनिया उजड़ चुकी है।

वसंत पंचमी के दिन बीएचयू के स्थापना दिवस पर वैदिक रीति रिवाजों से मां सरस्वती का हुआ पूजन

वाराणसी । कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए इस वर्ष वसंत पर्व पर बीएचयू का स्थापना दिवस सामान्य तरीके से आयोजित किया गया। इस दौरान बीएचयू परिवार ने उत्साह व उल्लास के साथ विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस (बसंत पंचमी) मनाया। स्थापना स्थल पर विधिवत वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने मां सरस्वती की पूजा कर सबकी सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। हवन पूजन और अनुष्ठान के बाद कुलपति ने संक्षिप्त भाषण के जरिए सर्वविद्या की राजधानी बीएचयू के स्थापना दिवस से अब तक के सफर को भी याद किया।

वहीं बसंत पंचमी के स्थापना दिवस के मौके पर कुलपति प्रो. राकेश भटनागर ने ट्रामा सेन्टर परिसर में नवनिर्मित नर्सेज भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक व अमृत फार्मेसी का उदघाटन किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय आज वसंत पंचमी के मौके पर अपना 105 वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीएचयू कुलपति ने स्थापना स्थल पर जहां वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की वहीं नर्स फ्लैट-एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का उद्घाटन कर स्थापना दिवस के आयोजनों में हिस्सा लिया। वहीं प्रत्येक वर्ष इस दिन निकलने वाली आकर्षक झांकी को लेकर आगंतुकों और परिसर में वसंत का उल्लास नदारद रहा। बसंत पंचमी और बीएचयू के स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को कुलपति कार्यालय की ओर से बीएचयू के स्थापना दिवस की एक श्वेत श्याम तस्वीर भी जारी की गई। इस तस्वीर में स्थापना दिवस के मौके पर पं. महामना मदन मोहन मालवीय नजर आ रहे हैं। बीएचयू के संस्थापक पं. महामना मदन मोहन मालवीय स्थापना दिवस समारोह में हाथ में कुछ कागज लिए भावपूर्ण मुद्रा में खड़े नजर आ रहे हैं। कुलपति ने स्थापना दिवस के मौके पर लोगों को शुभकामना देते हुए लिखा है - काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस व वसंत पंचमी पर विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को अनन्त शुभकामनाएं। -प्रो. राकेश भटनागर कुलपति।

खाली सिलिंडरों के साथ गैस गोदाम के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र-राज्य सरकार को लिया आड़े हाथ

देहरादून । रसोई गैस सिलिंडर के दामों में पचास रुपये की वृद्धि का महानगर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने गोविंदगढ़ गैस गोदाम के सामने खाली गैस सिलिंडरों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार महंगाई पर काबू पाने में असफल रही है। सोमवार दोपहर तीन बजे महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता गोविंदगढ़ स्थित गैस गोदाम के बाहर एकत्र हुए। इसके बाद सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लालचंद शर्मा ने कहा कि देशभर में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। भाजपा की केंद्र व राय सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल साबित हुई हैं।

सौ दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली मोदी सरकार ने महंगाई से देश की जनता का बुरा हाल कर दिया। कहा कि 2014 में 450 रुपये का रसोई गैस सिलिंडर आज 779 रुपये में मिल रहा है। पेट्रोल 89 रुपये व डीजल 79 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। कहा कि कोरोना महामारी के कारण आमजन के रोजगार ठप हो चुके हैं, पहले से महंगाई की मार झेल रहा आम आदमी अब पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से त्रस्त है। कहा कि यूपीए शासन में जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कचे तेल के दाम 150 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम काफी कम थे परंतु वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कचे तेल के दाम बहुत कम होने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस के दामों मे लगातार वृद्धि की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार, पार्षद कोमल बोरा, सविता सोनकर, मीना रावत, अमृता कौशल, अनीता निराला, गुरचरण कौशल, तरुण भारद्वाज, निर्मला देवी आदि मौजूद रहे।

विस चुनाव के लिए वोट की सियासत चढ़ने लगी परवान, सभी दल सिक्रिय हुए

नैनीताल । आगामी 2022 के विस चुनाव के लिए वोट की सियासत परवान चढ़ने लगी है। खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल वोटों की फसल उगाने के लिए अलग राज्य आंदोलन के दौरान के मुद्दों को जोरशोर से उठा रहे हैं। चुनाव तैयारी को लेकर अब तक निष्क्रिय उक्रांद भी अब सियासी समर में कूद पड़ा है। 2022 के चुनावों को लेकर राज्य में अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खुद को सत्ता की स्वाभाविक दावेदार बता कार्यकर्ताओं में जोश जगाने की कोशिश कर रही है मगर गुटबाजी के साथ ही जनाधार वाले नेताओं की कमी उसकी चुनावी धार को कुंद कर रही है। उधर दिल्ली की सत्ताधारी आप ने कांग्रेस को सत्ता की दौड़ से बाहर बताकर स्थान बनाने में जुटी है। आप ने तमाम क्षत्रपों को अपने पाले में लाकर चुनाव को लेकर गंभीर होने का संकेत दिया है।

आप की नजर पहाड़ के बजाय कुमाऊं में तराई तथा गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार की सीटों पर अधिक है। क्षेत्रीय दल उक्रांद के शीर्ष नेताओं में भले ही एका हो गई हो मगर उनकी सुस्ती व संगठन को लेकर बेरुखी आधार मजबूत बनाने में रोड़ा बनी है। इधर सत्ताधारी भाजपा विपक्षी दलों की ओर से बनाए जा रहे माहौल से आशंकित तो है मगर उसकी रणनीति मोदी मैजिक के संगठन के दम पर फिर से जीत हासिल करने की है।

राज्य के विस् चुनाव में बेरोजगारी व पलायन फिर से मुद्दा बनेगा। आप के साथ ही उक्रांद व कांग्रेस ने भी बिजली पानी मुफ्त के वादे के साथ उतरने के संकेत दिए हैं। बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य भी मुद्दा बनेगा। रोजगार के मोर्चे पर असफलता भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बहरहाल मुद्दे पुराने हैं, ऐसे में राजनीति की पिच पर बेटिंग तेज होने के आसार बने हैं।

सीरियल मर्डर की धमकी देने वाला यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही गोरखपुर में गिरफ्तार

गोरखपुर । गोरखपुर में लगातार तीन हत्या करने की धमकी देकर सनसनी फैलाने वाले बर्खास्त सिपाही दिग्विजय राय ने मोहद्दीपुर के रहने वाले दुकानदार से 50 हजार रुपये रंगदारी मांगी थी। सोमवार को कैंट पुलिस ने रंगदारी का केस दर्ज कर देर रात आरोपित सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। इंटरनेट मीडिया पर हत्या करने की धमकी देने का वीडियो वायरल होने पर रविवार को मोहद्दीपुर चौकी प्रभारी ने बर्खास्त सिपाही पर मुकदमा दर्ज कराया था। बर्खास्त सिपाही किसको मारने की फिराक में था, यह जानने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है।

यह है मामला- यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही दिग्विजय राय कुशीनगर जिले तरयासुजान, बसडीला गुनागर गांव का रहने वाला है। शनिवार की शाम फेसबुक पर लाइव होकर उसने 2.45 मिनट का वीडियो शेयर किया। जिसमें गोरखपुर पुलिस को चैलेंज करते हुए तीन दिन में तीन लोगों की हत्या करने की धमकी दी।

दिग्विजय ने कहा था कि 14 फरवरी की

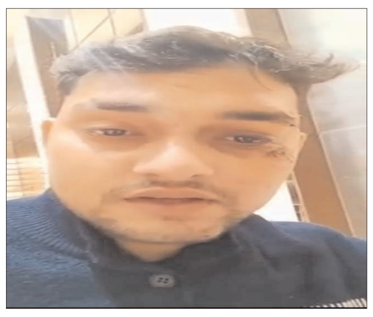

सुबह 10 बजे के पहले मोहद्दीपुर में एक हत्या करेगा। डीआइजी/एसएसपी के आदेश पर मोहद्दीपुर चौकी प्रभारी ने अरविंद सिंह ने रविवार की देर रात कैंट थाने में दिग्विजय राय के खिलाफ धमकी देने व आइटी एक्ट का केस दर्ज कराया। सोमवार की सुबह कैंट थाने पहुंचे मोहद्दीपुर निवासी रिंकू मिश्रा ने तहरीर देकर बताया कि रविवार को दिग्विजय राय उनकी दुकान पर आया था।

तीन दिन के भीतर 50 हजार रुपये न देने पर हत्या करने की धमकी दी है। रंगदारी मांगने का केस दर्ज कर कैंट पुलिस ने सोमवार की रात आरोपित सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वह तीन दिन से शहर के एक होटल में रूका था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो मोबाइल बंद कर होटल छोड़कर चला गया। प्रभारी निरीक्षक कैंट अनिल उपाध्याय ने बताया कि बर्खास्त सिपाही ने किसको मारने की धमकी दी थी, उसकी वजह क्या थी यह जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया जाएगा।

बढ़ा दी गई गई इंस्पेक्टर व ड्राइवर के परिवार की सुरक्षा - बर्खास्त सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद बस्ती जिले में तैनात इंस्पेक्टर व थाने के ड्राइवर के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दोनों लोगों का परिवार शहर में रहता है। कप्तानगंज थाने में अर्मायादित व्यवहार करने पर इंस्पेक्टर ने एसपी को रिपोर्ट भेजी थी। जिसके आधार पर दिग्विजय राय निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के बाद दिग्विजय ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो शेयर कर कप्तान, थानेदार समेत सात पुलिकर्मियों को गोली मारने की धमकी देने लगा। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने बर्खास्त कर दिया। दिग्विजय अपने ऊपर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार थानेदार समेत सात पुलिसकर्मियों को बताता है। 14 फरवरी को उसे सूचना मिली थी कि थानेदार व ड्राइवर गोरखपुर में मौजूद हैं। जानकारी होने पर अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर दोनों के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी थी।

कप्तानगंज से विधानसभा चुनाव लडऩा चाहता है- अनुशासनहीनता और एसपी हेमराज मीणा सहित कुछ अन्य पुलिस कर्मियों को जान से मारने की धमकी देने वाले बर्खास्त सिपाही दिग्विजय राय एक बार फिर सुर्खियों में है। गोरखपुर में तीन लोगों की हत्या करने की धमकी और दुकानदार से रंगदारी मांगने के बाद फिर से चर्चा में है। अपने फेसबुक वाल पर उसने एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है कि बस्ती जिले के कप्तानगंज विधानसभा से चुनाव लडऩा चाहता है। जिसके लिए चुनाव सामाग्री जुटा रहा है। पोस्टर, कैलेंडर आदि छपवा लिया है। अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा है।

हजारीबाग में एक रसोई में बनेगा 565 स्कूलों का पौष्टिक भोजन

हजारीबाग । हजारीबाग के डेमोटांड में अक्षयपात्र का महारसोईघर तेजी से आकार ले रहा है। बताया जा रहा है कि सात से आठ माह में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस रसोईघर में एक साथ 565 स्कूलों का मिड डे मील तैयार होगा। हजारीबाग में इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। तब तत्कालीन केंद्रीय नागर विमानन राय मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता व तत्कालीन उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला की उपस्थिति में अक्षय पात्र फाउंडेशन के स्वामी व्योमपद दास व जिला शिक्षा अधीक्षक ने करार पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में सांसद जयंत सिन्हा की पहल पर ही योजना पर तेजी से काम चल रहा है। करार के मुताबिक 565 विद्यालय के एक लाख बचों को यहां से खाना परोसा जाएगा। इससे बचों को स्वादिष्ट भोजन तो मिलेगा ही। साथ ही शिक्षक भी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकेंगे। इससे बचों की पढ़ाई की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इस रसोईघर से पूरे जिले में बचों को भोजन पहुंचाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट से एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 11 छात्रों को बड़ी राहत, आयोजित होगी परीक्षा

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण के प्रोटोकॉल के कारण एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 11 छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति को लेकर शीर्ष कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एम्स गोरखपुर में कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से वंचित रहे 11 छात्र-छात्राओं की फिर से परीक्षा होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को निर्देश दिया कि वह उन 11 प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित करे जिनकी उपस्थिति कम थी। परीक्षा से वंचित प्रथम वर्ष के मेडिकल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एम्स गोरखपुर को निर्देश दिया है कि वह प्रथम वर्ष के 11 याचिकाकर्ता व छात्रों समेत अन्य समान स्थिति वाले छात्रों की परीक्षा आयोजित करे जिनकी अटेंडेंस कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को 11 याचिकाकर्ता व छात्रों समेत अन्य समान स्थिति वाले छात्रों की परीक्षा करानी चाहिए। छात्र अगर परीक्षा में पास होते है तो उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले को मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यह परिस्थिति भिन्न है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के शॉर्ट अटेंडेंस के छात्रों परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने याचिककर्ता से ऐसे छात्रों की कुल संख्या बताने को कहा था जिनकी अटेंडेंस कम है। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील नेदुम्पार ने कहा था कि उनके क्लाइंट की पर्याप्त अटेंडेंस है और उनको परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जानी चहिए।

विपक्षी पार्टी के वकील उदित्य बनर्जी ने कहा था कि छात्र की उपस्थिति कोरोना से पहले 60 फीसदी थी और कोविड के बाद वह चार कक्षाओं में उपस्थित हुए। छात्र का तर्क है कि वह क्लास ही नहीं कर सकता क्योंकि वह रिमोट एरिया से आता है। अगर वह चार ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकता तो वह दूसरी क्लास में भी शामिल हो सकता था।

कोर्ट ने एम्स के वकील से पूछा था कि अगर आप आज सुनवाई में शामिल हो रहे हैं तो क्या आप सभी सुवनाई में शामिल हो सकते हैं। हर रोज कुछ न कुछ तकनीकी दिक्कत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अब छात्र के पास क्या विकल्प है। इसके बाद एम्स के वकील ने कहा था कि छात्र प्रथम वर्ष का है, लिहाजा अब उसकी अक्टूबर में होने वाली प्रथम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना चाहिए। इस बर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि यह 11 छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, क्या यह सिर्फ अटेंडेंस का मामला है, क्या कुछ और है। एलसीआइ के वकील के वकील गौरव शर्मा ने कहा था कि एम्स तो एमसीआइ के अधीन नहीं आता है, लेकिन हमारी राय है कि इन छात्रों का एक साल खराब नहीं होना चहिए।

मायावती के बेहद खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी यूपी कांग्रेस की मीडिया सेल के चेयरमैन

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के कभी बेहद खास रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कद अब कांग्रेस में भी बढ़ रहा है। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सिद्दीकी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विभाग के चेयरमैन बनाया है। इसके साथ ही सतीश अजमानी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बसपा मुखिया के कभी दाहिना हाथ रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अहम पद देकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मास्टरस्ट्रोक खेला है। प्रदेश में बुंदेलखंड के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से विधान परिषद सदस्य थे। बसपा से बाहर होने के बाद पार्टी ने उनकी सदस्यता भी समाप्त करा दी थी। इसके बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया सेल का चेयरमैन बनाया गया है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तथा उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। इसी क्रम में पहले मीडिया सेल को मजबूत किया जा रहा है।

करीब हफते भर पहले कांग्रेस ने पार्टी में उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया सेल को संभाल रहे अध्यक्ष मोहित पाण्डेय को हटाकर अभय पाण्डेय को काम सौंपा था। उत्तर प्रदेश मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस अब संगठन को भी पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रखना चाहती है। राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा प्रदेश से लेकर निचले स्तर तक के पदाधिकारी की लगातार रिपोर्ट ले रही हैं। यह बेहद स्पष्ट संदेश है कि निष्क्रिय व परिणाम न देने वालों को पद पर न रखा जाए। इसी समीक्षा में कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मोहित पाण्डेय फेल साबित हुए। अब उनके स्थान पर राष्ट्रीय आइटी सेल में काम कर रहे जालौन के अभय पाण्डेय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मोहित पाण्डेय को प्रियंका वाड्रा के निजी सचिव संदीप ड्क्षसह का बेहद खास बताया जाता है। उन्हीं ने यह जिम्मेदारी भी दिलाई थी, लेकिन प्रभारी की उम्मीदों पर खरा न उतरने की वजह से उन्हें हटा दिया गया है।

अब रामलला भी पहनेंगे खादी के वस्त्र, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित किए वस्त्र

लखनऊ। वसंत ऋतु के खुशनुमा मौसम के साथ ही रामलला की पोशाक भी बदलने जा रही है। प्रभु राम सहित माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी जाने-माने फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी द्वारा डिजाइन किए गए खादी सिल्क के वस्त्र धारण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से डिजाइनर द्वारा वसंत पंचमी पर मंगलवार को यह वस्त्र अयोध्या में रामलला को अर्पित किए जाएंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि रामलला के यह वस्त्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सहयोग से तैयार कराए गए हैं, जो कि प्रभु को अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर डिजाइनर मनीष को सौंप दिए। बॉलीवुड कलाकारों के लिए ड्रेस डिजाइन करते रहे मनीष त्रिपाठी मूल रूप से अंबेडकरनगर के निवासी हैं, लेकिन ज्यादा समय लखनऊ में ही रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यहां रहने की वजह से प्रभु राम की नगरी अयोध्या से गहरा लगाव रहा है। पिछले दिनों अवधनगरी गए तो मन में ख्याल आया कि प्रभु राम के लिए खादी के वस्त्र डिजाइन किए जाएं। इसके पीछे सोच यही थी कि खादी एकमात्र एथिकल फैब्रिक है।

यह प्रभु को धारण कराने से खादी का प्रचार-प्रसार होगा। चूंकि भगवान से सभी की आस्था जुड़ी है, इसलिए इस तरह से खादी की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी, जिससे खादी वस्त्रोद्योग से जुड़ी महिलाओं को भी काम मिलेगा। वह कहते हैं कि देश में हजारों-लाखों मंदिर हैं। यदि अयोध्या की तरह वहां सभी स्थलों पर भी खादी के वस्त्रों का प्रयोग शुरू होगा तो खादी को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीराम एयरपोर्ट के विकास को सौ करोड़ और मिले - राजकीय हवाई पट्टी को श्रीराम एयरपोर्ट में तब्दील करने के लिए किसानों से दूसरे चरण की भूमि खरीदने के लिए प्रदेश सरकार से सौ करोड़ रुपये और मिले हैं। 525 करोड़ रुपये इससे पहले जिला प्रशासन को मिल चुके हैं।

दोनों धनराशि मिलाकर 625 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से लगभग 450 करोड़ रुपये किसानों की सहमति से खरीदी गई भूमि के मुआवजे के रूप में वितरित किये जा चुके हैं। दो चरणों में एयरपोर्ट विकास के लिए किसानों से भूमि खरीदने के लिए लगभग एक हजार करोड़ खर्च का आकलन है। अभी लगभग चार सौ करोड़ रुपये प्रदेश सरकार से और मिलने हैं। एडीएम कानून व्यवस्था व प्रभारी विशेष भूमि अध्याप्ति जेपी ड्क्षसह के अनुसार शेष धनराशि भी जल्दी मिलने की संभावना है।

आठ राजस्व गांव जनौरा, गंजा, धर्मपुर सहादत, फिरोजपुर, कुसमाहा, सरेठी, पूरा हुसैन खां व नंदापुर के किसानों से लगभग 234 एकड़ भूमि अभी खरीदी जानी है। दो चरणों के विकास के लिए लगभग 600 एकड़ में से करीब 450 एकड़ भूमि किसानों की है। अवशेष भूमि सार्वजनिक बतायी गई है। पहले चरण में एटीआर-72 विमानों को लैंड करने के लिए दो किमी का रनवे चाहिए जिसमें डेढ़ किमी का रनवे पहले से मौजूद है। दूसरे चरण में ए-321 विमानों का संचालन किया जाना है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप सिंह करोला प्रस्तावित एयरपोर्ट का निरीक्षण करने जनवरी के अंतिम सप्ताह में आये थे। उसी के बाद आई तेजी में 100 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार ने किसानों से जमीन खरीदने के लिए और अवमुक्त किये हैं।

बिहार में कभी राम विलास पासवान की बोलती थी तूती, आज बेटे चिराग के समक्ष बंगला बचाने की चुनौती

पटना । सब राजनीति की माया है। कभी रामविलास पासवान की सियासत में तूती बोलती थी। इसी सियासी जमीन के बूते उन्होंने वर्ष 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और उसे दमदार तरीके से खड़ा किया था। लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी मंझधार में है। उनके पुत्र चिराग पासवान कई राजनीतिक चुनौतियों से घिरे हैं। हालात कुछ इस तरह हैं कि चिराग के लिए अब अपना बंगला बचाने की चुनौती बढ़ गई है।

बिहार चुनाव के नतीजे के बाद चिराग ने पांच दिसंबर को एलजेपी के प्रदेश कार्य समिति, सभी प्रकोष्ठों एवं जिला इकाईयों को भंग कर दिया था। तब जानकारों का कहना था कि कुछ नेताओं के असंतोष को दबाने और पार्टी को संभावित टूट से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। ढाई माह बीत गए, लेकिन चिराग ने अब तक प्रदेश एलजेपी की नई टीम खड़ी करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि चिराग प्रदेश अध्यक्ष के लिए नये और दमदार चेहरे की तलाश में हैं जो परिवार से बाहर का हो। चिराग एलजेपी पर लगे परिवारवाद का ठप्पा मिटाना चाहते हैं। पार्टी का चेहरा बदलने की फिराक में जुटे चिराग कुशवाहा, राजपूत और भूमिहार में से किसी एक जाति से अपने विश्वास पात्र नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। बहरहाल, एलजेपी और चिराग पासवान की राजनीतिक गतिविधियां प्रदेश में बिल्कुल शांत हैं।

पार्टी में भगदड़, नेताओं पर अन्य दलों के डोरे- एलजेपी के विक्षुब्ध नेताओं पर अन्य दलों की नजरें भी हैं। उनपर डोरे भी डाले जा रहे हैं। हाल में एलजेपी के दर्जन से यादा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। एलजेपी के पूर्व महासचिव केशव सिंह के नेतृत्व में दर्जनों नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे। इसी तरह एलजेपी के कई और नेताओं ने भी पार्टी छोड़ने का मन बनाया है।

केशव सिंह ने बताया कि चिराग की अपनी महत्वाकांक्षा ने चुनाव में एलजेपी की नैया डुबोई। इस डूब से एलजेपी उभर नहीं पायी है। पुराने नेताओं की कद्र भी नहीं है। रामविलास पासवान की कार्यशैली की तारीफ करते हुए केशव सिंह ने बताया कि चिराग में नेतृत्व क्षमता की कमी है, इसलिए एलजेपी में टूट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके अलावा जेडीयू के संपर्क में कई बड़े नेता, पूर्व विधायक एवं सांसद भी हैं। कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में शायद ही मिले जगह, घटी पूछ- जेडीयू के एलजेपी के प्रति कड़े रुख के चलते अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भी उसकी पूछ घट गई है। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार होने पर उसमें एलजेपी को शायद ही जगह मिले, क्योंकि इस मामले में जेडीयू ने कड़ा रूख अख्तियार कर रखा है।

राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि चुनाव में एलजेपी ने जिस तरीके से खासकर जेडीयू के खिलाफ वोटकटवा की भूमिका निभाई, उसके चलते एनडीए में उसकी कद्र कम हुई। इसका प्लॉट खुद चिराग ने तैयार किया था।

एलजेपी की नई टीम और जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द- पूरे मामले में एलजेपी की नपी-तुली प्रतिक्रिया मिली है। पार्टी के प्रदेया प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल कहते हैं कि एलजेपी बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान के कुशल नेतृत्व में पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। बिहार एलजेपी की नई टीम और सभी जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द होगी। इसके बाद पार्टी प्रदेश की राजनीति में अपने पुराने रंग में दिखेगी।

कंटेनर चालक ने नकली रिवाल्वर लहरा जीटी रोड पर मचाया कोहराम, राइफल के बल पर पुलिस ने किया काबू

तोपचांची । तोपचांची थाना के सामने जीटी रोड (एनएच-2) पर मंगलवार को कोहराम मच गया। एक कंटेनर चालक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में रिवाल्वर लहराते हुए दौड़ रहा था। उसे काबू में करने के लिए तोपचांची थाने की पुलिस पीछे-पीछे भाग रही थी। वह जब ललकारते हुए दौड़ता तो पुलिस के कदम पीछे पड़ते। इस दौरान उसने एक बस को भी हाइजेक करने की कोशिश की। जीटी रोड पर गुजर रहे वाहन चालकों और लोगों के तरफ भी रिवाल्वर तान दशहत फैला दी। इस दौरान जीटी रोड पर जाम लग गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से राइफल के बल पर ड्राइवर को काबू किया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

तोपचांची थाना के कबीरडीह निवासी अब्दुल वाहिद के ऊपर उसके ससुराल वालों ने दहेज प्रताड़ना तथा ससुराल वालों की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवा है। तोपचांची थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अब्दुल वाहिद को कई बार फोन किया। वह पूछताछ में सहयोग करने के बजाय पुलिस को ही फोन पर धमका देता था।

तोपचांची थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगलवार को अब्दुल वाहिद कंटेनर संख्या एचआर-55 वाई 1127 लेकर कोलकाता से औरंगाबाद जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने तोपचांची थाना के पास जीटी रोड पर बैरियर लगा दिया। थाना के पास पुलिस की चेकिंग को देख आरोपी अब्दुल वाहिद अपनी कंटेनर को थाना से 100 कदम की दूरी पर रोककर तलवार, भुजाली तथा नकली रिवाल्वर लेकर सड़क पर दौड़ गया। रिवाल्वर लहराते हुए पुलिस को ललकारने लगा।

अब्दुल का रौद्र रूप देख थोड़ी देर के लिए पुलिस सकते में आ गई। उसकी गतिविधि देख आस-पास की दुकानों की शटर गिरने लगी। इलाके में दहसत फैल गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। 10 मिनट कर सड़क का नजारा युद्ध के मैदान जैसा था। कभी अब्दुल पुलिस को रगेदता तो कभी पुलिस अब्दुल को। पुलिस गोली मारने की भी धमकी दे रही थी लेकिन अब्दुल मान नहीं रहा था। इस बीच पुलिस को लगा कि अब्दुल के हाथ में नकली रिवाल्वर है। पुलिसकर्मियों ने बड़ी हिम्मत से उसपर राइफल तान घेराबंदी की। इसके बाद उसे पकड़ कर थाना लाया गया। इस दौरान वह अपनी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ जोर-जोर की आवाज में गालियां बक रहा था।

बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए सौरव गांगुली तीसरी पसंद, ममता पहले नंबर पर कायम

कोलकाता । बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(बीसीसीआइ) के अध्यक्ष सौरव गांगुली के राजनीति के मैदान में उतरने को लेकर अक्सर ही चर्चा होती रहती है। चर्चा इस बात की होती है कि आखिर दादा राजनीति में कब आएंगे और अगर आएंगे भी तो किस पार्टी के साथ पारी शुरू करेंगे।

गांगुली भले ही जवाब न दे रहे हों कि लेकिन राज्य की जनता अपनी राय जरूर दे रही है। एबीपी न्यूज़-सीएनएक्स के सर्वे में 77 फीसद लोगों को कहना है कि सौरव गांगुली को राजनीति में आना चाहिए। सर्वे में 76.53 फीसद लोगों ने दादा के राजनीति में आने की वकालत की।

वहीं 21.28 फीसद लोगों ने कहा कि गांगुली को राजनीतिक पारी की शुरुआत नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 2.19 फीसद लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। अब जब 77 फीसद लोगों का मानना है कि सौरव गांगुली को राजनीतिक पारी की शुरुआत करना चाहिए, वहीं कुछ लोग दादा को चुनाव के बाद राज्य का मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं।

सर्वे के मुताबिक, 12.72 फीसद लोग चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद गांगुली राज्य की कमान संभालें। मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद में गांगुली तीसरे पायदान पर हैं। सर्वे में लोगों की पहली पसंद राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं।

उन्हें 38 फीसद लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं। दिलीप को 18.68 फीसद लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। सुवेंदु अधिकारी 10.13 फीसद लोगों की पसंद हैं।

बंगाल में 22 फरवरी के बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव का एलान- कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। वहीं बंगाल में चुनाव तिथि की घोषणा कब होगी इस पर सब की निगाहें टिकी है। खबर आ रही है कि बंगाल में चुनाव का एलान 22 फरवरी के बाद हो सकता है। क्योंकि, 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं।

जिसमें वह कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद ही चुनाव तिथि की घोषणा होने की बात कही जा रही है। बंगाल में वैसे भी विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी करीब-करीब पूरी कर ली है। इधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक के बाद योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही हैं। क्योंकि चुनाव तिथि घोषित होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगा।

ममता भी चुनावी सभा में पहले ही कह चुकी हैं कि जल्द ही मतदान की तिथि की घोषित हो सकती है और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। ममता ने कुछ दिन पहले ही मालदा की रैली में कार्यक्रताओं से अपील करते हुए कहा था कि आगामी कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग तैयार रहें। माना जा रहा है कि आगामी सप्ताह चुनाव का एलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा के नाम पर एक- एक परिवार को जोड़ने की कोशिश में लगी है। कूचबिहार से 11 फरवरी को प्रारंभ हुई परिवर्तन यात्रा रथ के आगमन को लेकर दार्जिलिंग और डाबग्राम फूलबाड़ी में पार्टी नेताओं की तैयारी जोरों पर है।

यहां दार्जिलिंग के तीन और सिलीगुड़ी महकमा के तीन यानि कुल छह विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लेकर एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। इसमें प्रमुख वक्ता के रुप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाने की तैयारी है। इसके लिए सभा मे होने वाले भीड़ को देखते हुए स्थान का चयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से भाजपा बंगाल की वर्तमान सरकार पर कटमनी और तुष्टिकरण नीति पर जमकर हमला बोलने वाली है। परिवर्तन यात्रा के सभा में योगी आदित्यनाथ के साथ स्थानीय सांसद व बंगाल के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आधिकारिक रुप से जब-तक योगी आदित्यनाथ का आना सुनिश्चित नहीं होता है तब-तक भाजपा की ओर से इस संबंध में कोई भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। भाजपा इस सभा के माध्यम से चुनाव पूर्व इसे सेमीफाइनल बनाने में जुटी है। भाजपा एक ही नारे पर काम कर रही है 2019 में हाफ तो 2021 में तृणमूल कांग्रेस को साफ करना है।

कांग्रेस सरकार के समर्थन के बावजूद शाहजहांपुर बॉर्डर पर नहीं पहुंच रहे किसान

जयपुर । कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आदोंलन राजस्थान में नहीं जम पा रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के सहयोग और समर्थन के बावजूद किसान आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समर्थन के कारण ही राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील पिछले कई दिनों से अपने साथियों के साथ शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं,हालांकि उनके साथियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। राजाराम मील कांग्रेस के पूर्व विधायक गंगाजल मील और सरकार के निकट माने जाने वाले कारोबारी सुरजाराम

मील के बड़े भाई है। मील परिवार के दामाद अमित ढ़ाका मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात है।

पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी ढ़ाका तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर राजस्थान आए हैं। सरकार में होने वाले राजनीतिक फैसलों में ढ़ाका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राजाराम मील जाट बहुल इलाकों में बार-बार संदेश पहुंचाकर लोगों को शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचने की अपील कर रहे हैं, लेकिन किसान नहीं पहुंचे रहे। जाट बहुल नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर जिलों में भी किसान आंदोलन आंदोलन का असर देखने का नहीं मिल रहा। हालांकि पंजाब और हरियाणा से सटे श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों से जरूर कुछ किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन अब वे लौटने लगे हैं। माकपा किसान आंदोलन को हवा देने में लगी है। हालांकि माकपा के प्रभाव वाले सीकर जिले से भी किसान आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे।

आंदोलन में किसानों के नहीं जुटने से चिंतित आंदोलन से जुड़े नेता अब समर्थन जुटाने के लिए जिलों में जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पिछले सप्ताह अलवर आ कर गए और अब अब माकपा नेता अमराराम की पहल पर वे 23 फरवरी को सीकर पहुंचेंगे। माकपा के पूर्व विधायक अमराराम व पेमाराम प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्रों में घूमकर किसानों को शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे का आग्रह करने में जुटे हैं।

उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शाहजहांपुर से सटे इलाकों के पार्टी विधायकों एवं अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्षों को प्रतिदिन आंदोलन स्थल पर पहुंचने को लेकर ड्यूटी सौंपी है। अलवर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता नियमित रूप शाहजहांपुर बॉर्डर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ सबसे शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट अब आंदोलन से अलग हो गए हैं। जाट ने यह कहते हुए खुद को आंदोलन से अलग किया कि वे इसका राजनीतिकरण नहीं चााहते हैं ।

ममता सरकार ने आइपीएस स्तर पर फिर किया फेरबदल, शीर्ष स्तर के कई अधिकारी हुए इधर से उधर

कोलकाता । बंगाल की ममता सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए आइपीएस स्तर पर फिर फेरबदल किया है। बंगाल पुलिस में सीआइएफ यूनिट के आइजी मनोज कुमार वर्मा को कोलकाता पुलिस में अतिरिक्त आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह दुर्लभ मौका है, जब एक आइपीएस अधिकारी बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस, दोनों में पदभार संभालेंगे। आइजी (सशस्त्र पुलिस) देवाशीष बोराल का कोलकाता पुलिस में तबादला किया गया है। वे कोलकाता पुलिस में सहायक आयुक्त का पदभार संभालेंगे। बोराल इससे पहले कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त का पदभार संभाल चुके हैं। महमूद अख्तर कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (ट्रेनिंग) का पदभार संभालेंगे। इससे पहले वे डीआइजी (सीआइएफ) के पद पर थे। पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवाओं के डीआइजी नीलाद्री चक्रवर्ती को कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) नियुक्त किया गया है। इसी तरह बंगाल एसटीएफ के एसपी अजीत सिंह यादव का सीआइएफ में उसी रैंक पर तबादला किया गया है। सीआइडी में एसएस के पद पर तैनात एस सेलवामुरूगन को अग्निशमन सेवाओं में एसपी के पद पर नियुक्त किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में बंगाल में आइपीएस स्तर पर कई दफा फेरबदल किया जा चुका है। यहां तक कि कोलकाता पुलिस आयुक्त भी बदले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय चुनाव आयोग के तबादले को लेकर कोई कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से ही सारे फेरबदल किए हैं।

जयमाता महाकाली मंदिर स्थापना दिवस पर महाआरती-भंडारा आज

दो दिवसीय धार्मिक आयोजनों में देवी जागरण 17 को

जबलपुर ,एजेंसी । जय माता महाकारी जवाहरगंज वार्ड, लार्डगंज कछियाना में बसंत पंचमी पर 18वें जयमाता महाकाली मंदिर स्थापना दिवस पर दो दिवसीय आयोजन 16 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। उपरोक्त जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष पं. शैलेन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार प्रातः महाकाली मां का दूध, शहर एवं नर्मदा जल से अभिषेक किया जायेगा। माता के श्रृंगार, पूजा अर्चन के साथ विशाल भंडारे का भोक अर्पित कर दोपहर 12 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा। रात्रि में महाआरती होगी। 17

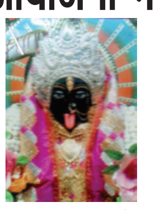

फरवरी को रात्रि 8 बजे से देवी जागरण सुप्रसिद्ध गायक मनीष अग्रवाल एंड पार्टी के द्वारा किया जायेगा। आयेजन समिति संरक्षक पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश यादव, मप्र युवा कांग्रेस नेता जय घनघोरिया, युवा समाजसेवी विजय घनघोरिया सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में होगा। आयोजन संचालक श्रीमती संगीता-मनोज नामदेव, संरक्षण पं. श्याम सुंदर त्रिपाठी, युवा समाजसेवी रत्नेश अग्रवाल, समिति अध्यक्ष शैलेन्द्र त्रिपाठी आदि ने सभी श्रृद्धालुजनों से उपस्थिती की अपील की है।

सहकारी समितियों की हड़ताल से निपटने की प्रशासनिक तैयारी

राशन वितरण और किसानों के पंजीयन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार

व्यवधान पैदा करने वालों पर होगी एफआईआर

जबलपुर ,एजेंसी । सेवा सहकारी समितियों और सहकारी उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को राशन के वितरण तथा गेहूं उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर ली गई है। इसे हड़ताल से निपटने प्रशासनिक तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासनिक आदेश में गरीबों को उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न का वितरण जहां ग्राम सहायक, पंचायत सचिव एवं अन्न उत्सव के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से करने, वहीं किसानों के पंजीयन का कार्य अब जिले में स्थित सभी एमपी ऑनलाइन कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर में भी करने के आदेश जारी किए गए हैं। अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने बैठक में गरीबों को राशन वितरण और किसानों के पंजीयन की इस वैकल्पिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वाले सोसायटी कर्मचारियों एवं उचित मूल्य दुकान के संचालकों अथवा विक्रेताओं के विरूद्ध सीधे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये हैं।

तत्काल हो कार्यवाही

अपर कलेक्टर ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन प्राप्त कर स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश भी दिये हैं। अपर कलेक्टर कि ओर से बताया गया कि यदि कोई उचित मूल्य दुकान का विक्रेता पीओएस मशीन जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाये। साथ ही वैधानिक कार्यवाही भी की जाये। अपर कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिये।

व्यवधान उत्पन्न किया तो सेवा तत्काल समाप्त

अपर कलेक्टर ने साफशब्दों में कहा कि किसानों के पंजीयन कार्य में यदि समितियों द्वारा आउटसोर्स से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर व्यवधान करते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाये और आउटसोर्स पर ही नये कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जायें। उन्होंने सभी अधिकारियों से गरीबों को राशन के वितरण और किसानों के पंजीयन कार्य में व्यवधान करने वाले हड़ताली सहकारी समितियों के कर्मचारियों एवं विक्रेताओं के विरूद्ध सख्ती बरतने के स्पष्ट निर्देश भी दिये हैं।

गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव, राजनीति में दंगल बन उभरा परिवार का विवाद

अहमदाबाद । गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं 21 फरवरी को अहमदाबाद सूरत वडोदरा राजकोट जामनगर तथा भावनगर महानगर पालिका के लिए मतदान होगा जबकि आगामी 28 फरवरी को 31 जिला पंचायत 231 तहसील पंचायत तथा 81 नगरपालिका के लिए मतदान होगा। गुजरात के सूरत में पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने पत्नी को वार्ड 15 से टिकट दिया तो पति कांग्रेस से टिकट लेकर उसके खिलाफ मैदान में हैं। पति- पत्नी कुछ समय से अलग रह रहे हैं, घर में शुरू हुआ टकराव अब राजनीति के दंगल तक पहुंच गया है।

सूरत महानगरपालिका के वार्ड 15 से 28 वर्षीय मनीषा आहीर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके पति 32 वर्षीय महेश आहिर ने कोरोना महामारी के बाद लगे लोकडाउन में अपनी नौकरी खो दी थी तथा मार्केटिंग सर्वे का बिजनेस शुरू किया। महेश सूरत में बतौर शिक्षक अपना कार्य करते थे लेकिन नौकरी जाने के बाद वे अपना बिजनेस करने लगे तथा कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य बन गए। हालांकि इस दौरान उनके चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था लेकिन जब उनकी पत्रकार पत्नी मनीषा अहीर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया तो पहले महेश उसके चुनाव प्रचार करने का फैसला किया लेकिन जब मनीषा और उसके परिवार वालों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई तो महेश उसी वार्ड से अपनी पत्नी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार बन कर खड़े हो गये।

मनीषा अहीर का कहना है कि महेश से करीब 7 साल पहले विवाह हुआ था तथा उनके बीच तकरार रहने लगा महेश उसे घर में भी खुश नहीं रख पा रहा था तथा उसके साथ झगड़े करता था। अब चुनाव में उसके खिलाफ खड़े होकर भी उसका विरोध कर रहा है जो मेरी समझ से परे है। इस दंपत्ति को एक 5 साल का पुत्र भी है तथा इनकी शादी पारंपरिक रीति रिवाज से ही संपन्न हुई थी। परिवार का दंगल अब चुनावी मैदान पर भी उतर आया है तथा सूरत के वार्ड 15 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है।

कांग्रेस की जीत हो या भाजपा की लेकिन जीत और हार खुशी और गम अहीर परिवार में ही रहेगा साथ ही वार्ड 15 के जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य भी इसी परिवार को मिलने की संभावना है। उधर सौराष्ट्र के बोटाद में शहर भाजपा अध्यक्ष अतुल पटेल की पत्नी रोनक बेन को भाजपा ने हैं अपना उम्मीदवार बनाया तो अतुल ने पार्टी को ही टिकट वापस लौटा दिया। दरअसल यहां से अतुल चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उनकी पत्नी को मैदान में उतार दिया जिससे नाराज अतुल ने पार्टी को टिकट वापस लौटा दिया।

नाले में मिला अज्ञात का शव

जबलपुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद कदम दूर सड़क किनारे नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नशे की हालत में व्यक्ति संभवतः नाले में गिर गया हो और उसकी मौत हो गई हो। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर उसे पीएम के लिये भिजवाते हुए उसकी शिनाख्ती के प्रयास शुरु कर दिये है।पुलिस ने बताया कि इंद्रा मार्केट निवासी सब्जी विक्रेताओं ने सुबह पुलिस को सूचना दी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाले में पड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाते हुए आवश्यक कार्रवाई कर शिनाख्ती के प्रयास शुरु कर दिये है। प्रारंभिक तौर पर अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि मृतक भिक्षुक होगा, जो कि सड़क किनारे ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहा होगा। जिसकी नशे या फिर किसी अन्य कारण से नाले में गिरकर मौत हो गई। क्योकि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नही है।

वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराने को लेकर दबाव बनाने में जुटे समर्थक, कोटा में करेंगे बड़ी रैली

जयपुर । राजस्थान भाजपा में चल रही खींचतान के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक अब खुलकर मैदान में आने की तैयारी में जुटे हैं। ये खेमा चाहता है कि भाजपा आलाकमान वसुंधरा राजे के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा अभी कर दे। तीन साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराने को लेकर आलाकमान पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई गई है।

इसी लिहाज से 8 मार्च को अपने जन्मदिन के दिन वसुंधरा राजे पूर्वी राजस्थान की यात्रा शुरू करेगी। यह यात्रा दो से तीन दिन की होगी, जिसमें वे चार जिलों में जाकर जनसमर्थन टटोलने के साथ ही पार्टी नेतृत्व को संदेश दिया जाएगा। इसे धार्मिक यात्रा का रूप दिया जा रहा है। इसके बाद अप्रैल में कोटा में बड़ी रैली करने की योजना बनाई जा रही है। शुरू से ही जनसंघ और भाजपा के गढ़ रहे कोटा में रैली करने को लेकर वसुंधरा समर्थकों ने दो दिन पहले चिंतन शिविर किया। इस चिंतन शिविर में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान रैली की रूपरेखा पर विचार किया गया। पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीकृष्ण पाटीदार सहित कई वसुंधरा समर्थकों ने इस दौरान प्रदेश नेतृत्व पर खुद की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और राजावत ने दैनिक जागरण से कहा कि वसुंधरा को आगे रखकर चुनाव लड़ने पर ही पार्टी को सफलता मिल सकती है। वे ही प्रदेश की एकमात्र लोकप्रिय नेता है। अप्रैल में होने वाली रैली को वैसे तो प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आयोजन बताया जा रहा है, लेकिन इसका असली मकसद वसुंधरा समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन है। राजावत का कहना है कि 50 हजार लोगों की इस रैली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह और राज्यसभा सांसद ओमप्रकाश माथुर को आमंत्रित किया जाएगा।

वसुंधरा के विश्वस्तों में शामिल श्रीकृष्ण पाटीदार ने कहा कि पार्टी नेतृत्व वसुंधरा को दूर रखकर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में परिणाम भुगत चुका है। दोनों में भाजपा की हार हुई। पार्टी की ऐसी दुर्गति को देखकर कार्यकर्ता चिंतित है। कांग्रेस सरकार से मुक्ति के लिए वसुंधरा ही एकमात्र सहारा है। वे ही पार्टी में नई जान डाल सकती है। पूर्व विधायक विघाशंकर नंदवाना, कंवरलाल मीणा बारां के जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा और बूंदी के पूर्व जिला अध्यक्ष महीपत सिंह को रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वसुंधरा की पूर्वी राजस्थान की धार्मिक यात्रा का जिम्मा पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनूस खान ने संभाला है।

वसुंधरा दिल्ली में सक्रिय

एक तरफ जहां उनके समर्थक प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे दिल्ली में सक्रिय है। वसुंधरा राजे ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा से मुलाकात की। पिछले सप्ताह वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुकी है। वसुंधरा राजे पिछले कई दिनों से दिल्ली में रहकर पार्टी के केंद्रीय नेताओं के सम्पर्क में हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपना पक्ष रखने में जुटी हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया व उप नेता राजेंद्र राठौड़ द्वारा अपने समर्थकों को पार्टी के निर्णयों से दूर रखने का मुद्दा भी वे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठा रही हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री और सीएम आज करवाएंगे गृहप्रवेश

प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मिलेगी सौगात

जबलपुर। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत जबलपुर जिले के 3 हजार 656 हितग्राहियों सहित मध्यप्रदेश के एक लाख हितग्राहियों को उनके नये आवास में गृह प्रवेश करवायेंगे। गृह प्रवेश महोत्सव का प्रदेश स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम भोपाल स्थित मिन्टो हॉल में प्रातः 11 बजे से होगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। जबलपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में पीएम आवास योजना के जिले के पाँच हितग्राही भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन मप्र और फेसबुक, ट्वीटर पर किया जायेगा।

सबको आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराया गया है। लाभान्वित सभी परिवार ऐसे थेए जिनके पास घर नहीं था या वे कच्चे जीर्ण.शीर्ण घरों में रह रहे थे। पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आवासों को भी शामिल कर लिया जाए तो आवास निर्माण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य में शुमार होगा। योजनान्तर्गत हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी जिलों में एक लाख 20 हजार तथा दूरस्थ पहुँचविहीन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में एक लाख 30 हजार रूपये शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में आवास निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दिये जाते हैं। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण भी किया जाता है। हितग्राही को उज्जवला योजनान्तर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश में समृद्ध पर्यावास अभियान के नाम से इन हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, परिवार की महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व.सहायता समूहों के रूप में संगठित करने जैसी 27 शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। यह इंद्रधनुषी प्रयोग हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास में महत्पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। योजनान्तर्गत चार किश्तों में आवास सॉफ ट.एप के माध्यम से जियो टेग, फोटो अपलोड होने पर स्वमेव राशि हितग्राही के खाते में अंतरित हो जाती है। इससे हितग्राही को योजनांतर्गत राशि प्राप्त करने के लिये परेशान नहीं होना पड़ता है।

15 लीटर हाथ भट्टी शराब और 12 क्विंटल महुआ लहान जब्त

आबकारी विभाग की कार्रवाई

जबलपुर ,एजेंसी ।

आबकारी विभाग के अमले ने सोमवार को अवैध कच्ची शराब निर्माण की सूचना के आधार पर खेरमाई मंदिर के पास बापू नगर रांझी में दबिश देकर अलग-अलग स्थानों से 15 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा प्लास्टिक एवं लोहे के 6 ड्रम मे भरे हुए 1200 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर आबकारी अधिनियम के तहत तीन प्रकरण पंजीबद्ध किये हैं । आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी के नेतृत्व में की गई, इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जी डी लाहौरिया, रामजी पांडेय, इंद्रजीत तिवारी, भारती गौंड उपनिरीक्षक आर एस मरावी, रविशंकर यादव, श्वेता तिवारी तथा आबकारी मुख्य आरक्षक, आरक्षक एवं होम गार्ड के जवान उपस्थित रहे।

पाटन में सहकारिता समिति कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

पाटन ,एजेंसी ।

सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों को नियमित एवं शासन की समस्त योजनाओं का लाभ भी दिए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर मनीष यादव, नितिन यादव, मनीष पटेल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

सहकारिता विभाग कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान : सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से पाटन तहसील के किसान यूरिया, खाद, बीज के लिए परेशान हैं वहीं दूसरी ओर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राही भी परेशान हो रहे हैं। राशन की समस्या चरम सीमा पर चल रही है हड़ताल से किसान वर्ग एवं गरीब वर्ग परेशान है।

कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में 24 को मिला रोजगार

जबलपुर ,एजेंसी ।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार कैम्पस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत सोमवार को कुल 64 आवेदकों ने पंजीयन कराया। यहां मौजूद तीन कंपनियों ने पंजीकृत युवाओं का साक्षात्कार लेकर 24 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया। उपसंचालक रोजगार एमएस मरकाम ने बताया कि मंगलवार 16 फरवरी को भी कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जायेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव का आयोजन कटंगा स्थित जिला रोजगार कार्यालय उद्योग भवन कटंगा में किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से चयनित 24 आवेदकों में से 12 को भारतीय जीवन बीमा निगम जबलपुर, मेजर डिजायर में 8 एवं यशस्वी ग्रुप में 4 आवेदकों को रोजगार मिला।

तापसी पन्नू

ऋचा चड्ढा मंत्री के बयान पर हुई आग बबूला, सोशल मीडिया पर जाहिर किया गुस्सा

हाल में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने बेहद विवादित बयान दिया है. इससे बॉलीवुड की दो दबंग एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू काफी नाराज हो गई हैं.

मंत्री की टिप्पणी के प्रति अपना गुस्सा और निराशा जाहिर करने के लिए वे शनिवार को ट्विटर पर आईं. बता दें कि मंत्री ने कृषि कानूनों के विरोध के दौरान मरे किसानों को लेकर गलत बयानी की थी. उन्होंने कहा था कि अगर वे किसान घर वापस भी आ जाते, तो भी वे मर जाते.

मंत्री की टिप्पणी पर एक न्यूज क्लिप को रीट्वीट करते हुए तापसी पन्नू ने लिखा, मनुष्य के जीवन का मूल्य कुछ नहीं है! अनाज पैदा करने वाले लोगों का मूल्य कुछ नहीं हैं. उनकी मौत का मजाक बनाना वालों के क्या कहने!... अनमोल!

वहीं ऋचा ने लिखा, पूरी तरह से अपमानजनक! हम बेहतर के लायक हैं.

शनिवार को हरियाणा के भिवानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जय प्रकाश से पूछा गया था कि किसान आंदोलन के दौरान 200 किसानों की मौत को लेकर वे क्या कहेंगे इस पर उन्होंने कहा था, अगर वे (किसान) घर पर होते तो क्या उनकी मौत नहीं होती अगर वे अपने घरों पर होते तो भी वे मरते.

दो लाख लोगों में से एक, क्या छह महीने में 200 लोग नहीं मरते हैं? किसी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है और कोई बीमार पड़ने पर मर जाता है.

वे अपनी मर्जी से मर गए. मेरी उनसे गहरी संवेदना है.

बाद में, अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देते हुए, एक वीडियो में दलाल ने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मैंने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के निधन पर शोक व्यक्त किया था.

भले ही कोई व्यक्ति अस्वाभाविक रूप से मर जाए, यह दर्दनाक है. जहां तक शहीद का दर्जा देने की बात है, तो जवानों को यह दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए नीति बनाई हुई है.वह आगे कहते हैं, मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया और इसका गलत अर्थ निकाला गया. मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा. हरियाणा के कृषि मंत्री के रूप में मैंने अगर अपने बयान से किसी को आहत किया है तो मैं माफी मांगता हूं. मैं किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं.

दीया मिर्जा

की प्री-वेडिंग सेरेमनी की फोटोज आई सामने

बॉलीवुड में इस समय जश्न का माहौल है. कोई सेलेब शादी के बंधन में बंध रहा है तो किसी के घर में नन्हा मेहमान आने की खुशी है. इस बीच एक और अच्छी खबर आ रही है कि दीया मिर्जा शादी के बंधन में बंधन में बंधने वाली हैं. वह मुंबई के बिजनेसमैन वैभव रेखी से 15 फरवरी को शादी करेंगी.

माना जा रहा है कि यह शादी बेहद प्राइवेट रखी जाएगी और सिर्फ खास दोस्तों और परिजन ही शादी में मौजूद रहेंगे. यह दीया की दूसरी शादी है. वह 2019 में अपने पहले पति साहिल संघा से अलग हुई थीं.

इस समय दीया मिर्जा की प्री-वेडिंग पार्टी की कुछ फोटोज सामने आई हैं. बीते शनिवार को दीया ने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों संग प्रीवेडिंग पार्टी का खूब जश्न मनाया. स्टार फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस पार्टी की कुछ शानदार फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, प्री वेडिंग पार्टी में दीया मिर्जा अपने बॉयफ्रेंड और अपने नए परिवार के साथ. दीया इन प्री वेडिंग पार्टी फोटोज में काफी खुश नजर आ रही हैं. वह सफेद लेस ड्रेस में बेहद सुंदर लग रही हैं.

ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यह जोड़ी लॉकडाउन के दौरान एक-दूसरे के काफी करीब आए थे. इन्होंने तब एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताया था. बता दें कि वैभव मुंबई के बिजनसमैन और इन्वेस्टर हैं. याद दिला दें कि ये दीया की दूसरी शादी होगी, इससे पहले दीया की साहिल संघा से शादी हुई थी, लेकिन शादी के करीब 11 साल बाद दोनों ने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला लिया था.

तब दीया मिर्जा और साहिल दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अलग होने जा रहे हैं लेकिन हमारे बीच के रिश्ते हमेशा अच्छे रहेंगे. हमने कानूनी तौर से अलग होने का फैसला किया है.

लेकिन हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे. यह वैभव की भी दूसरी शादी है. उनकी पहली पत्नी एक योग और लाइफ स्टाइल कोच सुनैना रेखी हैं. इस रिश्ते से उनकी एक बेटी भी है.

रोहनप्रीत ने कराया नेहा कक्कड़ के नाम का टैटू, सिंगर बोलीं- बेबी, दर्द हुआ होगा?

छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक के सेलेब्स वैलेंटाइन्स डे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह ने उन्हें सरप्राइज देते हुए हाथ पर नेहा के नाम का टैटू कराया है। इसकी जानकारी सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। रोहनप्रीत सिंह ने कलाई पर लिखवाया है, नेहूज मैन।

नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत सिंह संग रोमांटिक होते हुए कई फोटोज शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, मेरे वैलेंटाइन ने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। इतना प्यार बेबी मैंने उनसे पूछा कि बेबी, दर्द हुआ होगा उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं नेहू बाबू के गाने गुनगुना रहा था। आप सच में नेहूज मैन हैं और मैं हमेशा के लिए आपकी हूं और रहूंगी। लव यू, बेबी। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे डियर।

इससे पहले नेहा कक्कड़ ने बूटी शेक गाने पर डांस करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें वह साफ-सफाई करते हुए गाने पर डांस कर रही थीं। रोहनप्रीत उनके पास बैठकर नेहा को देख रहे थे। नेहा कक्कड़ ने वीडियो पोस्ट करते कैप्शन में लिखा, रोहनप्रीत सिंह के साथ बूटी शेक। बधाइयां। इस पोस्ट पर इंडियन आइडल के पूर्व कंटेस्टेंट विभोर पराशर ने कॉमेंट करते हुए लिखा, क्यूटेस्ट कपल। वहीं, फैन्स कॉमेंट कर नेहा और रोहनप्रीत सिंह की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गौरतलब है कि नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने 24 अक्टूबर, 2020 को परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए थे। इन्होंने सेलिब्रेशन दिल्ली में किया था। सोशल मीडिया पर नेहा और रोहनप्रीत की शादी के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थे। दोनों रिलेशनशिप में सॉन्ग 'नेहू द व्याह' के दौरान आए थे। पहली मुलाकात गाने की शूटिंग के दौरान ही हुई थी।

वैलेंटाइंस डे पर पत्नी नताशा दलाल के लिए उमड़ा वरुण धवन का प्यार, फोटो शेयर कर कही यह बात

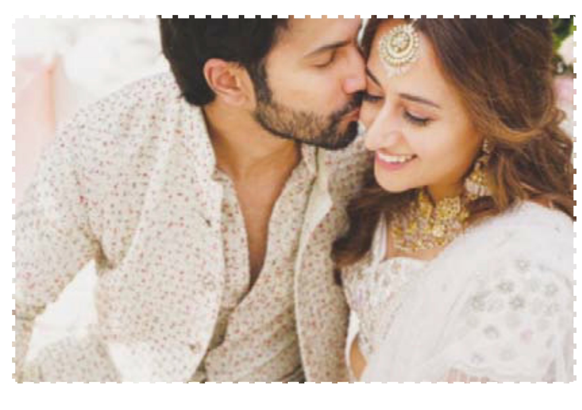

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन शादी के बाद पत्नी नताशा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों ने 24 जनवरी को मुंबई के अलीबाग में सात फेरे लिए थे। वरुण धवन ने रविवार को वैलेंटाइंस डे के मौके पर पत्नी नताशा को खास अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह नताशा के साथ नजर आ रहे हैं।

फोटो में वरुण धवन पत्नी नताशा दलाल को हग करते नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं। वरुण ने सिल्वर कलर का जैकेट पहन रखा है वहीं नताशा ग्रे लॉन्ग कोट में काफी खूबसूरत लग रही हैं। दोनों की यह तस्वीर शादी से पहले एक वेकेशन की दौरान की है। वरुण धवन ने इस फोटो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते कैप्शन में लिखा, हर दिन, हर जगह। इसके साथ ही उन्होंने हार्ट इमोटिकॉन भी शेयर किया है। फैन्स वरुण और नताशा की इस फोटो को बहुत पसंद कर रहे हैं।

वरुण ने शादी के बाद पत्नी नताशा संग शेयर की थी पहली फोटो

बताते चलें कि नताशा संग शादी के बाद वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वह पत्नी नताशा के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो में वरुण धवन और नताशा सिल्वर आउटफिट में नजर आए। तस्वीर में वरुण और नताशा के पीछे डेविड धवन और लाली को भी देखा जा सकता है। वरुण ने इस फोटो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, जीवनभर का प्यार आधिकारिक हो गया।इसके अलावा वरुण धवन ने ट्वीट कर फैन्स को शुक्रिया भी कहा था। उन्होंने लिखा, पिछले दिनों मुझे और नताशा को जो आप लोगों से प्यार और पॉजिटिविटी मिली है, वह मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं हर व्यक्ति को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। अपना प्यार ऐसे ही देते रहें।वरुण की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो पिछली बार वह फिल्म कुली नंबर 1 में नजर आए थे। फिल्म में वरुण के साथ सारा अली खान फीमेल लीड रोल में थीं। कुली नंबर 1 का निर्देशन डेविड धवन ने किया था। अब वरुण धवन जुग-जुग जियो मूवी में नजर आएंगे। इस फिल्म में अनिल कपूर, नीतू कपूर व अन्य सितारे अहम भूमिकाओं में दिखेंगे।

संक्षिप्त समाचार

अश्विन से पहले इन चार भारतीय गेंदबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में लगाये हैं शतक

चेन्नई, (एजेंसी)। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। अश्विन हालांकि अकेले ऐसे गेंदबाज नहीं हैं जिन्होंने शतक लगाया है। इससे पहले भी चार भारतीय गेंदबाजों ने शतक लगाये हैं। ये गेंदबाज हैं। हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, अजीत अगरकर और जयंत यादव। जयंत ने इंग्लैंड के खिलाफ 104 रन की पारी खेली थी। मुंबई में साल 2016 में खेले गए इस मैच जयंत ने 204 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौकों की मदद से 104 रन बनाए थे। वहीं स्पिनर हरभजन सिंह ने भी शतकीय पारी खेली है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में 2010 में खेले गए मैच की दूसरी पारी में नाबाद 115 रन बनाए थे। वहीं अनिल कुंबले ने साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ द ओवर में नाबाद 110 रन बनाए थे। वहीं अजीत अगरकर ने इंग्लैंड के खिलाफ वर्ष 2002 में लाडर्स के मैदान में 109 रन की पारी खेली थी।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची ओसाका

मेलबर्न, (एजेंसी)। जापान की महिला टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गयी है। ओसाका ने यहां सीधे सेटों में सीह सु वेई को 6-2, 6-2 से हराया। वेई के खिलाफ यह सेरेना की 19 वीं जीत है। अब सेमीफाइनल में ओसाका का मुकाबला अमेरिकी खिलाड़ी महिला सेरेना विलियम्स से हो सकता है। ओसाका का अगला मुकाबला सेरेना और दूसरी वरीयता प्राप्त सिमोना हालेप के बीच होने वाले मैच की विजेता से होगा। तीसरी वरीयता प्राप्त ओसाका ने सीह के खिलाफ शानदार सर्विस कर अपना दबदबा बनाया।

ओलंपिक उद्घाटन समारोह का होगा सीधा प्रसारण

वाशिंगटन, (एजेंसी)। ओलंपिक प्रोडक्शन के कार्यकारी प्रोड्यूसर और अध्यक्ष मोली सोलोमन ने कहा कि महामारी के बीच हो रहे ओलंपिक के महत्व को देखते हुए पहली बार उद्घाटन समारोह का सुबह सीधा प्रसारण करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा , कोरोना महामारी में लोगों का जीवन बदल गया है। लंबे समय तक लॉकडाउन में रहने के बाद ओलंपिक खेलों का महत्व बदल गया है। इससे तय है कि खेलों में यह अतुल्य ओलंपिक होंगे क्योंकि पहली बार किसी महामारी के संपूर्ण विश्व एकसाथ नजर आयेगा। अमेरिका में भी आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण होगा। अमेरिकी दर्शक 23 जुलाई को होने वाला यह समारोह सुबह सात बजे एनबीसी पर और चार बजे लॉस एंजिलिस में देखेंगे।

वेस्ली ने ओपेरा यूरो रैपिड शतरंज टूनार्मेंट जीता

नई दिल्ली, (संवाददाता)। अमेरिका के वेसली सो नें ओपेरा यूरो रैपिड शतरंज टूनार्मेंट का खिताब जीत लिया है। वेसली ने विश्व चैम्पियन मेगनस कार्लसन को लगातार दूसरे फाइनल में शिकस्त देते हुए यह जीत दर्ज की। फाइनल के पहले कार्लसन और वेसली सो के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा था, ऐसे मे दूसरे दिन के पहले ही मैच मे जोरदार खेल की उम्मीद थी। फाइनल में काले मोहरो से खेल रहे मेगनस कार्लसन नें सिसिलियन ओपेनिंग की 14वीं चाल मे दो प्यादों के लिए अपने ऊंट की कुबार्नी दे दी और यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और मात्र 28 चालों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हुए हुए तीनों मुकाबलों में कार्लसन नें कई बार दबाव बनाने की कोशिश की पर वेसली नें बेहद संतुलित खेलते हुए तीनों मैच ड्रॉ करा लिए और 2.5-1.5 से दूसरा दिन तो अपने नाम किया साथ ही खिताब भी अपने नाम किया। वहीं फ्रांस के मकसीम लागरेव को 2.5-1.5 और 2-0 से हराकर अजरबैजान के तैमूर रद्जाबोव तीसरे स्थान पर रहे।

नैसकार कप सीरीज मोटर रेस में 11 कारें टकरायीं

नई दिल्ली, (संवाददाता)। अमेरिका के फ्लोरिडा में नैसकार कप सीरीज मोटर रेस में माइकल मैकडॉवेल ने जीत दर्ज की। इस दौरान हुए एक दुखद हादसे में 11 कारें टकरा गयी। इन कारों की टक्कर फाइनल लैप में हुई। इसमें डेटॉना-500 आग की लपटों में घिर गई। सबसे पहले पेंसेके टीम के साथी जॉय लोगानो और ब्रैड केसेलोस्की की कारें टकराईं। वहीं इसी बीच ऑस्टिन सिंडीक की कार केसेलोस्की की कार से टकरा गई पर किसी ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आई है।

ओलंपिक टीम में जगह पाने प्रयास कर रहा : दिलप्रीत

बेंगलुरू, (एजेंसी)। हॉकी फारवर्ड दिलप्रीत सिंह स्ट्राइकर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में कई प्रमुख प्रतियोगिताएं नहीं हुईं। मैं अब प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा लेकर ओलंपिक टीम में एक स्थान पाने के लिए प्रयासरत हूं। दिलप्रीत ने कहा, हम उन कारकों के बारे में चिंता नहीं करना चाहते जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। मैं तब तक इंतजार नहीं करना चाहता जब तक मुझे अपने लिए एक मजबूत मामला बनाने के लिए भारत के लिए मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। मैं यहां अपने कौशल का प्रदर्शन करने और अपनी योग्यता साबित करने के लिए पहुंचा हूं। हम प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में 100 प्रतिशत दे रहे हैं। दिलप्रीत ने कहा कि मैं अपने तकनीक पर काम कर रहा हूं। मैंने काफी सुधार किया है। वरिष्ठ खिलाडिों को खेलते देखना, उनके साथ समय बिताना युवा खिलाडिों को आत्मविश्वास हासिल करने का मौका देता है। हम वरिष्ठ खिलाडिों से सुझाव और मार्गदर्शन लेते हैं, वह हमारे लिए सदैव मददगार रहते हैं।

शतरंज लीग शुरू करेगा एआईसीएफ : कपूर

नई दिल्ली, (संवाददाता)। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) ने कहा है कि वह इस साल इंडियन शतरंज लीग शुरू करेगा। इसके साथ ही यह भी कहा है कि वह ओलंपियाड के अगले उपलब्ध चरण की बोली भी लगायेगा। नव नियुक्त एआईसीएफ अध्यक्ष संजय कपूर ने यहां अपनी सालाना आम बैठक (एजीएम) के आयोजन के बाद देश को शतरंज का सुपरपावर बनाने के प्रारुप का भी अनावरण किया। कपूर ने कहा, हम भारत को विश्व के लिये शतरंज का ठिकाना बनाना चाहते हैं। हमने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये एक योजना भी बनायी है। उन्होंने साथ ही कहा, लंबे समय से हम इस खेल को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ इंडियन शतरंज लीग शुरू करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, हालांकि फ्रेंचाइजी टीमों का पहला चरण इस साल ही आयोजित किया जायेगा। साथ ही कहा कि आम बैठम में फैसला किया गया कि महासंघ महिलाओं की प्रतियोगिता आयोजित करेगा।

चेन्नई में भारत और इंग्लैड मैच में ऑलीपोप के आउट होने के बाद उत्साहित होते हुए अक्षर पटेल और आर अश्विन।

दर्शकों की मैदान पर वापसी से उत्साहित हैं गांगुली

नई दिल्ली , (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसआई) अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा है कि एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी तबियत अब ठीक है और उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया है। गांगुली कोरोना महामारी के कारण एक साल के बाद दर्शकों के मैदान पर लौटने से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, दर्शक वापस मैदान पर आ गए हैं। ये देख कर अच्छा लग रहा है। तीसरे टेस्ट के लिए अहमदाबाद में दर्शकों के लिए टिकटें बिक गई हैं। अहमदाबाद में सीरीज के बाकी दो टेस्ट मैच होने हैं। इसमें से 24 फरवरी से शुरू होने वाला मैच दिन-रात्रि मैच होगा। गांगुली ने कहा, दिन-रात्रि टेस्ट है। मुझे खुशी हो रही है। नया मोटेरा स्टेडियम तैयार है ।

गांगुली दिन-रात्रि टेस्ट मैच के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने ही कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पहले दिन-रात्रि टेस्ट मैच का आयोजन करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। गांगुली ने कहा, मैंने कोलकाता टेस्ट मैच की बात कही जब गुलाबी गेंद से पहला टेस्ट हुआ था। गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच का रोमांच और अस्तित्व बढ़ेगा। उन्होंने गुजरात क्रिकेट असोसिएशन (जीसीए) की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जीसीए इस टेस्ट मैच के लिए काफी सहायता कर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारतीय टीम को मिली जीत से बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में जो कमाल हुआ वह विशेष था। साथ ही कहा कि 18 फरवरी को आईपीएल के 14वें सत्र के लिए होने वाली नीलामी की पूरी तैयारी हो गयी है।

शमी–नवदीप की तीसरे टेस्ट में हो सकती है वापसी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय चोटिल हुए टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और युवा तेज नवदीप सैनी फिट हो गये हैं। ऐसे में अब शमी और नवदीप को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में जगह मिल सकती है। माना जा रहा है कि इसी कारण टीम प्रबंधन ने शमी और सैनी को विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेने से रोक दिया था। अंतिम दो टेस्ट मैचों के लिए टीम की घोषणा शीघ्र होने की संभावना है। इन दोनों ही गेंदबाजों को इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था। दोनों गेंदबाज आजकल राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी (एनसीए) में अभ्यास कर रहे हैं। सैनी वर्तमान में बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में हैं। उन्होंने गेंदबाजी शुरू कर दी है। दिल्ली के चयनकर्ता विजय हजारे ट्रॉफी के लिए सैनी को टीम में शामिल करना चाहते थे पर उन्हें फिलहाल एनसीए में ही रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है। शमी को 19 दिसंबर को एडिलेड में भारत की दूसरी पारी के दौरान पैट कमिंस की शॉर्ट गेंद लगी थी। इससे उनकी कलाई में फ्रेक्चर हो गया था, इसके बाद से ही वह टीम से बाहर थे। वहीं नवदीप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में ग्रोइन इंजरी के बाद बाहर हो गये थे।

पारंपरिक परिधानों में नजर आये धोनी और साक्षी

नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी पारंपरिक परिधानों में नजर आये हैं। धोनी और साक्षी ने इसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं हैं। एक ग्रुप फोटो में धोनी के साथ सिंगर और ऐक्टर जैसी गिल और कुछ अन्य दोस्त भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में धोनी ने डिजाइनर कुर्ता-पजामा के साथ मैचिंग ओवरकोट पहना हुआ है। वहीं साक्षी गुलाबी लहंगे में नजर आ रही हैं। धोनी खेल से दूर होने के बाद भी पहले की तरह ही लोगों के दिलों में छाये हुए हैं। पिछले साल आईपीएल में उनकी टीम चेन्नै सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। आईपीएल के इतिहास में पहली बार टीम प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी।

मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला एकल मुकाबले में जापान की नाओमी ओसाका खेलती हुई।

आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई के सामने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों का मामला उठाया

नई दिल्ली, (संवाददाता)। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) की दक्षिण अफ्रीकी टीम की पाकिस्तान के खिलाफ अप्रैल में एकदिवसीय और टी-20 श्रृंखला की घोषणा के बाद ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ-साथ ही आईपीएल की अन्य फ्रेंचाइजियों ने भी आधिकारिक रूप से भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की उपलब्धता का मामला उठाया है। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने भी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2021 सत्र के लिए दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी कैगिसो रबाडा और एनरिच नोर्त्जे की उपलब्धता को लेकर जानकारी मांगी है। अभी 7 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी पांच आईपीएल फ्रेंचाइजी के प्रमुख खिलाड़ियों की सूची में हैं, जिसमें रबाडा और नोर्त्जे के अलावा फाफ डू प्लेसिस और लुंगी एनगिडी, क्विंटन डी कॉक ,एबी डिविलियर्स और डेविड मिलर शामिल हैं। इन सभी खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजियों ने इस सत्र के लिए रिटेन (बरकरार) रखा है। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच 2 से 16 अप्रैल के बीच तीन एकदिवसीय और 4 टी-20 मैच खेले जाने हैं।

आईपीएल 9 या 10 अप्रैल से आईपीएल शुरू हो सकता है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने से आईपीएल फ्रेंचाइजियां प्रभावित हो सकती हैं। वहीं सीएसए ने खिलाड़ियों की उपलब्धता के संदेह पर कहा कि वह बीसीसीआई के साथ सीधे बातचीत कर आईपीएल संबंधी मुद्दों को हल कर लेगा, हालांकि इस पर आईपीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हेमांग अमीन का अभी कोई जवाब नहीं आया है।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुकाबला तुर्की से

(नई दिल्ली, (संवाददाता)। भारत की सीनियर महिला फुटबॉल टीम कोविड-19 महामारी के बाद अपने पहले टूनार्मेंट के लिए तैयार है और 17 फरवरी से तुर्की के अलान्या में तीन अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगी। सर्बिया के खिलाफ 17 फरवरी को पहले मैच के बाद भारतीय टीम 19 फरवरी को रूस से भिड़ेगी जबकि 23 फरवरी को उक्रेन का सामना करेगी। टीम पिछले दो महीने से गोवा में तैयारी कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मैच टीम के लिए काफी अहमियत रखते हैं क्योंकि भारत को अगले साल 20 जनवरी से छह फरवरी तक महिला एशियाई कप की मेजबानी करनी है। मुख्य कोच मेमूल रॉकी ने कहा कि तुर्की में होने वाले मुकाबलों से वे परख पाएंगे कि महामारी के कारण लंबे ब्रेक के बाद उनके खिलाड़ी मैच फिटनेस को लेकर किसी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा, हमारी टीम युवा और प्रतिभावान है। यह लंबे समय में हमारा पहला टूनार्मेंट होगा लेकिन लड़कियां खुद को साबित करने के लिए बेताब हैं।

सबसे बड़ी छह जीत में से पांच विराट की कप्तानी में मिलीं

नई दिल्ली, (संवाददाता)। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने टेस्ट इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। यहां खेले गये दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने मेहमान टीम इंग्लैंड को 317 रनों से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने साल 1986 में लीड्स में 279 रन से जीत हासिल की थी। सबसे अहम बात यह है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी छह जीत में से पांच विराट की कप्तानी में हासिल की हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने को ध्यान देना चाहिये। कोहली की अगुवाई में ही भारत ने 2015 में रांची टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 337 रन, इंदौर में साल 2016 में न्यूजीलैंड को 321, नार्थ साउंड टेस्ट में 2019 में वेस्टइंडीज को 318 रन से हराया था। इसके अलावा श्रीलंका के गाले में साल 2017 में भारतीय टीम ने 204 रनों से जीत दर्ज की थी। इसी के साथ ही कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक और रिकॉर्ड की बराबरी की है। धोनी की कप्तानी में भारतीय धरती पर टीम इंडिया ने 30 टेस्ट मैचों में 21 में जीत हासिल की थी। वहीं कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने भारतीय धरती पर 28 में से 21 टेस्ट मैच जीते हैं। विराट देश में सबसे सफल कप्तान हैं। उन्हें साल 2014 में कप्तानी दी गई थी। तब से भारतीय टीम ने 58 में से 34 मैच जीते हैं जबकि 14 में उसे हार मिली है।

बेयरस्टॉ और वुड इंग्लैंड टीम में शामिल, मोईन को आराम

चेन्नई। इंग्लैंड ने अहमदाबाद में 24 फरवरी से शुरू होने वाले दिन-रात्रि के टेस्ट मैच के लिये विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टॉ और तेज गेंदबाज मार्क वुड को अपनी टीम में शामिल किया। इंग्लैंड की टीम ने दूसरे टेस्ट में मिली करारी हार को देखते हुए यह बदलाव किये हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों को आराम देने वाली अपनी नीति के तहत स्पिन ऑलराउंडर मोईन अली को इस मैच में आराम दिया गया है। बेयरस्टॉ को पहले दोनो मैचों के लिए आराम दिया गया था। अब वह तरोताजा होकर तीसरे टेस्ट मैच में टीम से जुड़ेंगे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अपने एक बयान में कहा, मोईन वापस इंग्लैंड लौटेंगे जबकि बेयरस्टॉ और मार्क वुड टीम से जुड़ेंगे।

लंदन में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में गोल दागते हुए चेलेसा के टीमो वार्मर।

विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप दूसरे स्थान पर पहुंची टीम इंडिया

चेन्नई, (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में मिली 317 रन की शानदार जीत के साथ ही भारतीय टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम को अब फाइनल खेलने के लिए 2-1 से जीत दर्ज करनी होगी। भारतीय टीम अभी डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में 69.7 फीसदी कुल 460 अंक लेकर न्यूजीलैंड के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है। न्यूजीलैंड के 70 फीसदी कुल 420 अंक है। अंक तालिका की शीर्ष दो टीमों के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर जून में खिताबी मुकाबला होगा। ऐसे में भारतीय टीम को फाइनल में जगह बनाने के लिए एक और मैच जीतना होगा। इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम चौथे स्थान पर थी।

फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए शुभमन गिल, टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

चेन्नई, (एजेंसी)। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल, भारतीय टीम के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शुभमन गिल फील्डिंग के लिए नहीं उतरे। टेस्ट मैच के तीसरे दिन शुभमन गिल को फील्डिंग करते हुए बाएं हाथ की कलाई में चोट लग गई थी। इसके बाद अब अहमदाबाद में 24 फरवरी से होने वाले पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि 21 वर्षीय गिल का एहतियात के तौर पर स्कैन कराया गया है। गिल मैच की पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 14 रन बनाए।

बीसीसीआई ने बयान में कहा, दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन फील्डिंग करते समय गिल के बाएं हाथ पर गेंद लगी थी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी चोट का आकलन कर रहा है। युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल ने भारत की ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई थी। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 29 और 50 रन बनाए थे। इसके अलावा इसी मैदान पर गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में 0 और 14 रन के स्कोर बनाए थे।